राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 222 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार ,03 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र

भारत-बांग्लादेश सीमा पर चली गोलियां, सुरक्षा बल की मौत

अगरतला। दक्षिण त्रिपुरा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के समीप मवेशी तस्करों के साथ कहासुनी के बाद सीमा सुरक्षा बल के कर्मी द्वारा गोली चलाने से 23 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गयी। पुलिस के अनुसार सोमवार को देवीपुर गांव में जब मवेशी तस्करों का एक समूह मवेशियों की बांग्लादेश में तस्करी कर रहा था तो बीएसएफ कर्मियों ने उसे रोका। पुलिस का कहना है कि उसी बीच बीएसएफ कर्मियों एवं मवेशी तस्करों के बीच कहासुनी हो गयी और बीएसएफ के कर्मी ने गोली चला दी। गोली जाशिम मियां को लगी और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। जाशिम के पिता खलिक मियां ने आरोप लगाया कि वह गाय देखने सीमा के पास गये थे। तभी बीएसएफ कर्मियों ने उन्हें गालियां दीं। इस बीच उनका बेटा उन्हें बचाने पहुंचा लेकिन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी एवं बीएसएफ कर्मी ने गोली चला दी। ग्रामीणों ने दावा किया है कि स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके जाशिम का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होने वाली मवेशियों की तस्करी या किसी अवैध घटना कोई लेना-देना नहीं था। हालांकि सोमवार की रात को जारी की गयी बीएसफ की विज्ञप्ति के अनुसार सात आठ मवेशी तस्कर, मवेशियों की तस्करी के इरादे से सीमा के खंभे को नुकसान पहुंचा रहे थे और जब बीएसएफ कर्मियों ने विरोध किया तब वे उन पर लाठियों एवं छुरे से हमला करने के लिए टूट पड़े जिससे एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। विज्ञप्ति के अनुसार जब बड़ी संख्या में लोगों ने बीएसएफ कर्मियों को घेर लिया जब खतरा भांपकर उन्होंने गोलिया चला दीं और एक व्यक्ति घायल हो गया जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई।

किसान प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने पत्रकार मंदीप पूनिया की जमानत याचिका मंजूर की

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मंदीप पूनिया की जमानत याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतबीर सिंह लाम्बा ने कहा कि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह सभी पुलिसकर्मी हैं। न्यायाधीश ने कहा, ''इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी/प्रार्थी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है।'' सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पूनिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पूनिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186 (सरकारी कर्मचारी के काम में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करना), 353 (ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी को पीटना या उसके खिलाफ बल प्रयोग) और 332 (ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने पूनिया को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया। उसने कहा, ''आरोपी जमानत पर रिहाई के दौरान इस प्रकार का कोई अपराध या कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। आरोपी किसी भी तरह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।'' अदालत ने निर्देश दिया कि जब जांच एजेंसी को आवश्यकता होगी, तब आरोपी पेश होगा।

बार-बार हंगामे के बाद राज्यसभा बुधवार तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के कारण बार-बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। बार-बार स्थगन के बाद तीसरी बार कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा थमता नहीं देखकर इसे दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ गया। विपक्ष द्वारा सभापति एम. वेंकैया नायडू के स्थगन नोटिस को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद राज्यसभा को पहली बार पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दूसरा पूर्वागह्न 11.30 बजे तक था, और कार्यवाही शुरू होने के बाद तीसरा स्थगन दोपहर 12.30 बजे तक के लिए कर दिया गया। इसके बाद, सदन को विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

किसान प्रदर्शन स्थल किले में तब्दीलः सड़कों पर लोहे की कीलें, कंटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड्स के बीच लोहे की छड़ें लगाई गईं

नई दिल्ली (एजेंसी)। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने बार्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को दोबारा से दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। ताकि हर हाल में किसानों को राजधानी के भीतर दाखिल होने न दिया जाए। इसके लिए कंटीलें तारों से लेकर पक्की दीवार और रोड पर लंबी लंबी कीलें तक लगा दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सहित दूसरी सीमाओं पर दिल्ली की ओर आने वाली सड़कों पर कीलें लगवा दी हैं। ये कीलें एक एक फुट तक लंबी हैं. कहीं रोड खुदवा कर सीमेंट से ऐसी लगवाई हैं, जिससे इन्हें तोड़ा न जा सके, तो कहीं लोहे की मोटी चद्दर में बैल्ड कराकर इन चादरों को जमीन में बिछवा दिया गया है ताकि किसान के ट्रैक्टर किसी भी स्थिति में प्रवेश न कर पाएं। यदि पार करने का प्रयास करेंगे तो ट्रैक्टर ही पंचर हो जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बार्डर इलाकों में दो- दो फुट मोटी कंक्रीट की दीवार भी बनवा दी है। इनकी उंचाई तीन-तीन फुट है. ये दीवार इतनी मोटी और मजबूत बनवाई हैं कि ट्रैक्टर की टक्कर से टूटे नहीं। इतना ही नहीं बार्डरों पर मेट्रो लाइन के किनारे लगने वाले कंटीले तार भी लगवाए गए हैं। ये तार इसलिए लगवाए गए हैं ताकि किसानी पैदल दिल्ली कूच करना चाहे तो भी न जा पाए।

बॉर्डर पर लगे बैरिकेड के पास टिकैत ने जमीन पर बैठकर खाया खाना

कृषि कानूनों पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस की तरफसे बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कंक्रीट की दीवार और कटीले तारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दोपहर का खाना पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड के पास जमीन पर बैठ कर खाया। राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, ये लड़ाई अक्टूबर महीने तक चलेगी। जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। बीते 2 महीने से अधिक समय से किसान कृषि कानून का विरोध कर रहें हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ मिनट बाद ही शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य भी कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आए।

मोदी सरकार के शासन का स्टाइल, चुप कराओ, अलग करो और कुचल दो- राहुल गांधी

किसान से जुड़े प्रदर्शन ट्वीट करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह मोदी सरकार के शासन का स्टाइल है, उन्हें चुप कराओ, उनको अलग करो, उन्हें कुचल दो। आपको बता दें, राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। उधर दिल्ली की सीमाओं पर देश का अन्नदाता कृषि कानूनों के खिलाफ डटा हुआ है। इस बीच पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट पुलिस द्वारा सीमेंट एवं कंटीले तार के बैरिकेड्स बनाए जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसे दीवार की बजाय पुल बनवाना चाहिए। कांग्रेस सांसद गांधी ने

> किसान से जुड़े प्रदर्शन ट्वीट करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में एक खबर भी शेयर की है।

किसानों के आंदोलन स्थलों के निकट बैरिकेड्स बनाए जाने से जुड़ी कई तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार, पुल बनाइए, दीवार नहीं। आपको बता दें, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से ही युद्ध? आपको बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को सोमवार को किले में तब्दील कर दिया गया।

वेंकैया नायडू बोले, लोग कहते हैं कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई, वे राज्यसभा में कामकाज का रिकॉर्ड देख लें

नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले सत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों को उच सदन में बिना चर्चा के पारित कराये जाने संबंधी दावे गलत हैं. साथ ही उन्होंने सदस्यों से ऐसी किसी भी स्थिति को टालने की अपील की जिससे सदन एवं राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों.संसद के पिछले सत्र में तीन कृषि विधेयकों के पारित होने के समय उच सदन में भारी हंगामे की ओर परोक्ष संकेत करते हुए नायडू ने सदस्यों से वर्तमान बजट सत्र को ''अधिक अर्थवान बनाने को कहा जिसमें मुद्दों पर ''शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और मर्यादित तरीके से व्यापक चर्चा हो सके.

उप राष्ट्रपति ने अधिक विवरण नहीं देते हुए कहा, ''पिछली बार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं.सितंबर में हुए पिछले सत्र में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए लाये गये तीन विधेयकों को पारित किए जाने के समय विपक्ष के कुछ सदस्यों ने नियम पुस्तिका फाड़ दी थी और वे आसन के बेहद समीप आ गये थे और जमकर हंगामा किया था. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सदन में कृषि कानूनों पर कोई चर्चा नहीं हुई . उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदन के कामकाज का रिकार्ड देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार सदन में कृषि विधेयकों पर चार घंटे चर्चा हुई.

नायडू ने कहा कि उन विधेयकों पर मतविभाजन को लेकर अलग अलग नजरिए हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि वह पहले ही दोहरा चुके हैं कि सदन में कृषि कानूनों पर विस्तृत चर्चा हुयी थी.उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र का मतलब लोगों की उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भागीदारी होता है. सभापति ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट 2021-22 पर चर्चा के लिए 20 से अधिक घंटे का आवंटित समय सदस्यों को लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, जिसका सरकार जवाब देगी. उन्होंने रविवार को विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई उनकी चर्चा का भी उल्लेख किया.

नायडू ने कहा, ''मैं गंभीरता से आशा करता हूं कि पिछले चार सत्रों की भावना के अनुरूप यह महत्वपूर्ण बजट सत्र भी बहुत कामकाज वाला रहेगा.

बड़ी चुनौती, बड़ा इरादा; खजाना भरने के लिए आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं

नई दिल्ली। पिछले छह वर्षों में पूरी दुनिया यह बात बखूबी समझ गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी की टीम के काम करने का अंदाज अलग होता है। सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 का रंग भी वैसा ही है यानी जब चुनौतियां बड़ी हों, तो उसके सामने इरादे भी उतने ही बुलंद होते हैं। मकसद साफ है कि कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतर चुकी देश की इकोनॉमी ना सिर्फ रफ्तार भरे बल्कि लंबे समय तक इसमें तेज विकास दर हासिल होती रहे। कोरोना की तबाही ने देश के स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर जो चिंता पैदा की है, उससे निपटने का इसमें पूरा रोडमैप है।

नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने जिस तरह से निजीकरण व सुधारों की रफ्तार और तेज करने का एलान किया है, उससे साफ है कि कोरोना बाद के माहौल में भारत के लिए जो अवसर बन रहे हैं, घरेलू राजनीति की वजह से उन्हें गंवाने का जोखिम नहीं उठाया जाएगा। राजनीतिक रूप से इकोनॉमी और रोजगार बड़ी चुनौती है और बजट में उससे निपटने का खाका तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। बतौर वित्त मंत्री यह उनका तीसरा आम बजट था। इससे पहले सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में संसद भवन में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आम बजट 2021-22 के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने एक घंटा 50 मिनट चले बजट अभिभाषण की शुरुआत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले हर देशवासी के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और हाल ही में बेहद विपरीत हालात में आस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम की सफलता का भी उल्लेख किया।

उन्होंने अपने बजट को छह स्तंभों - स्वास्थ्य व कल्याण, भौतिक व वित्तीय पूंजी संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, इनोवेशन और अनुसंधान व विकास, न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन पर पेश किया। उनके अभिभाषण के राजनीतिक रंग भी कम नहीं थे। खास तौर पर जिस तरह से जिन राज्यों में चुनाव करीब हैं, उनके लिए गिन-गिन कर घोषणाएं की गई हैं। इससे सरकार की राजनीतिक सोच का भी पता चलता है कि वह विकास को ही चुनावी हथियार बनाएगी।

वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान-

कोरोना महामारी से उबरने में वैक्सीन की भूमिका को देखते हुए उन्होंने 35 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है। इससे पूरे देश में वैक्सीन कार्यक्रम तेज होगा। वित्त मंत्री ने कई मंत्रालयों के बजटीय आवंटन में कटौती भी की है, जिससे खास तौर पर सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर असर पड़ेगा।

इस बार की बजट घोषणाएं एक तरह से मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के नारे का बड़ा विस्तार हैं। ढांचागत क्षेत्र के लिए फंडिंग में 34 फीसद की वृद्धि की गई है जो खजाने की सेहत को देखते हुए नाकाफी नहीं कही जा सकती। इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए वित्त जुटाने के लिए एक नए वित्तीय संस्थान के गठन की घोषणा की गई है। बीमा सेक्टर में एफडीआई सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 फीसद करने और सरकारी बैंकों व बीमा कंपनियों के निजीकरण का एलान कर वैश्विक बिरादरी को यह संकेत भेजा गया है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब उनके लिए भारतीय बाजार के दरवाजे बंद करना नहीं है। भारतीय उद्यमियों और कंपनियों को वो सारे प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनसे भारत नई उभरती वैश्विक व्यवस्था में एक भरोसेमंद सप्लाई चेन स्थापित कर सके।

एनआईए करेगी इजरायली दूतावास के बाहर हुए आईईडी धमाके की जांच, गृह मंत्रालय ने दिया जिम्मा

नई दिल्ली। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच अब नेशनव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एनआईए को धमाके की जांच का जिम्मा सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक, एनआईए धमाके के पीछे ईरान ऐंगल को ध्यान में रखते हुए ही जांच आगे बढ़ाएगी। पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया, एनआईए को मामले की जांच इसलिए सौंपी गई हैं क्योंकि इसके अंतरराष्ट्रीय ऐंगल भी हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धमाके वाली जगह से विस्फोटक के नमूने, सीसीटीवी फुटेज और धमकी वाली चिट्ठी इकट्ठे किए हैं, जिन्हें अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे बहुत से सबूत हैं जो यह संकेत देते हैं कि मामले में तेहरान का हाथ है। हालांकि, जांचकर्ता अभी भी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने यह बम दूतावास के बाहर रखा था।

बता दें कि बीते हफ्ते शुक्रवार को इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था। घटना स्थल पर जांचकर्ताओं को इजराइली दूतावास का पता लिखा एक लिफाफा और लेटर भी मिला है, जिसमें ईरान के एक सैन्य जनरल और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिक्र है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह विस्फोट केवल एक ट्रेलर है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को आश्वासन दिया था कि धमाके के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी।

सीबीएसई की डेट शीट जारी: 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे

बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट आज जारी कर दी गई। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की डेटशीट केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी की गई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने देशभर के सीबीएसई छात्रों को शुभकामनाएं दी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू हो रही हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जनवरी 2021 को सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ संवाद में बताया था कि बोर्ड 2 फरवरी 2021 को कक्षा 10वीं और 12वीं का पूरा शेड्यूल जारी करेगा।

सीबीएसई ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि इस साल कक्षा 10 में 75 विषयों व कक्षा 12 में 111 विषयों की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। साथ कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए इस बार अधिकतम संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिससे कि परीक्षा केंद्रों पर ज्यादा भीड़ न लग पाए। सीबीएसई ने बताया कि 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कराने में कुल 45 दिनों का वक्त लगा था, लेकिन इस बार इसे घटाकर 39 दिन किया गया है। यानी पिछले साल से 6 दिन कम समय में परीक्षाएं संपन्न होंगी।

सीबीएसई 10वीं या 12वीं परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र अपनी परीक्षाओं का टाइम-टेबल/डेटशीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

पिछले वर्ष 10वीं की परीक्षा में करीब 18 लाख और 12वीं की परीक्षा में करीब 12 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। 10वीं की परीक्षा में कुल 91.46 फीसदी और 12वीं में 88.78 फीसदी विद्यार्थी पास हुए थे। सीबीएसई हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के टॉपरों का भी

विपक्षी सदस्य की नई दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध के बीच लोकसभा स्थगित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन से बाहर आते हुए ।

एसएलएस का फिर होगा हॉट फायर टेस्ट, फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षण करने की तैयारी में नासा

वाशिंगटन। अंतरिक्ष पर्यटन के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने पहले स्पेस लांच सिस्टम (एसएलएस) का फरवरी में एक बार फिर हॉट फायर टेस्ट करने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले जनवरी में यह परीक्षण किया जाना था लेकिन एजेंसी ने समय से पहले ही इसे बंद कर दिया

था। एसएलएस नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। इसी के तहत नासा सबसे शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर रहा है। इसके दो बड़े हिस्से हैं- एक तरल ईंधन इंजन और दूसरा ठोस ईंधन बूस्टर। एक रॉकेट में कई बूस्टर का उपयोग किया जाता है, जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा के आगे पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बल लगाते हैं।

नासा के एक अधिकारियों ने कहा, 'एसएलएस के परीक्षणों को आठ चरणों में पूरा किया जाना है। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने ग्रीन रन नाम दिया है। दिसंबर तक इसके सात चरणों का परीक्षण किया जा चुका है। अब अंतिम चरण यानी हॉट फायर टेस्ट फरवरी के चौथे सप्ताह की शुरुआत में किया जाएगा।

एलएलएस के इंजन की बीते दिनों टेस्ट फायरिंग हुई थी: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा की परिक्रमा करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए स्पेस लांच सिस्टम रॉकेट की मदद से ओरियन स्पेसक्राफ्ट लांच करेगा। इसके परीक्षण के लिए एलएलएस के इंजन की बीते दिनों टेस्ट फायरिंग हुई थी। इसमें चार आरएस-25 इंजन लगे हैं। रॉकेट के चारों इंजनों को वैसे ही फायर किया गया, जैसे वे लांच करते समय होंगे। इन इंजनों में पहली बार एक साथ एक मिनट तक फायरिंग हुई। हालांकि इसे बीच में ही रोक दिया गया। पहले हॉट फायर और सात ग्रीन रन परीक्षणों का मूल्यांकन करने के बाद नासा और कोर स्टेज के प्रमुख कांट्रैक्टर बोइंग ने माना कि हॉट फायर टेस्ट लंबे समय किया जाना चाहिए, तभी इसके सही परिणाम सामने आ सकते हैं।

अमेरिकी तट की ओर बढ़ रहा शक्तिशाली तूफान, न्यूयॉर्क व बोस्टन समेत कई शहरों में भारी बर्फबारी का अनुमान

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, बोस्टन और अमेरिका के पूर्वोत्तर के कई अन्य शहरों में सोमवार को लगभग दो फीट (60.96 सेमी) बर्फ की चादर से ढक सकता है। इसका कारण एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान है, जो अमेरिकी तट की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय मौसम

विभाग ने इसकी जानकारी दी है। रविवार देर रात से पूर्वोत्तर में बर्फबारी शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार विभाग के अनुसार पूर्वी पेंसिल्वेनिया, उत्तरी न्यू जर्सी, दक्षिणी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में 20 इंच से अधिक बर्फबारी का अनुमान है।

इस तूफान के कारण न्यूयॉर्क में जनजीवन ठप पड़ सकती है। ऐसे में यहां सोमवार को स्कूल बंद रहने की घोषणा कर दी गई है और कोरोना टीकाकरण का काम भी प्रभावित हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने रविवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे और अधिकारी कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए अपॉइंट्मेंट्स रीशेड्यूल कर रहे हैं। सोमवार को चारों ओर भारी खतरा और कठिनाई होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर में यात्रा करने लायक स्थिति नहीं होने की उम्मीद है। सोमवार तक 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तूफान धीरे-धीरे मंगलवार रात को उत्तरी न्यू इंग्लैंड की ओर बढ़ जाएगा और बुधवार को कमजोर पड़ जाएगा। कई क्षेत्रों में 2 इंच से अधिक बर्फ के साथ यह तूफान वाशिंगटन डीसी से टकराया।

म्यांमार में तख्तापलट: सेना ने एक साल के लिए इमरजेंसी लगाई

स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति हिरासत में

यांगोन। 10 साल पहले डेमोक्रेसी सिस्टम अपनाने वाले म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन लौट आया है। देश में एक साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना ने सोमवार तड़के देश की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, प्रेसिडेंट यू विन मिंट के साथ कई सीनियर नेताओं और अफसरों को हिरासत में ले लिया।

इसके बाद सेना के टीवी चैनल ने बताया कि मिलिट्री ने देश को कंट्रोल में ले लिया है। यू मिंट के दस्तखत वाली एक घोषणा के अनुसार, देश की सत्ता अब कमांडर-इन-चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मिन आंग ह्लाइंग के हाथ में रहेगी। देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट माइंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है।

देश में शासन कर रही पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीके स्पोक्स पर्सन म्यो न्यूंट ने न्यूज एजेंसी से इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि स्टेट काउंसलर और प्रेसिडेंट को सेना ने हिरासत में ले लिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, शान प्रांत के प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्टर यू सो न्यूंट ल्विन, काया प्रांत के हृष्ठ चेयरमैन थंग टे और अय्यरवाडी रीजन पार्लियामेंट के कुछ

यांगोन में सिटी हॉल के अंदर तैनात सैनिक

NLD रिप्रजेंटेटिव्स को हिरासत में लिया गया है।

न्यूंट ने यह भी कहा कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 मेंबर्स भी हिरासत में हैं। हमारे मेंबर्स ने बताया है कि मुझे भी हिरासत में लिए जाने की तैयारी है। मेरी बारी जल्द ही आएगी।

राजधानी में फोन और इंटरनेट बंद: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की राजधानी नेपाईतॉ में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई हैं। राजधानी और मुख्य शहरों में सड़कों पर सैनिक तैनात हैं। देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुबह सोमवार 8 बजे ऑर्डिनरी लेवल से 50त्न तक गिर गई। इसका पैटर्न टेलीकॉम ब्लैकआउट की ओर इशारा कर रहा है।

पिछले साल 8 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी (हृष्ठ) ने 83त्न सीटें जीत ली थीं। लोअर हाउस की मीटिंग सोमवार को बुलाई गई थी। सैन्य शासन खत्म होने के बाद देश में दूसरी बार ये चुनाव हुए थे। हालांकि, म्यांमार की सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इन चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

भारत ने लोकतंत्र बहाली की अपील की

भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर गहरी चिंता जताते हुए पड़ोसी देश से कानून और लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने अपील की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार हालात की बारीकी से निगरानी कर रही थी।

अमेरिका-आस्ट्रेलिया ने कहा - नेताओं को तुरंत रिहा करे सेना

व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जेन साकी ने कहा कि म्यांमार में सेना के कदम के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ब्रीफ किया गया है। इस मसले पर अमेरिका रीजनल पार्टनर्स से कॉन्टैक्ट में है। वहीं, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने म्यांमार सेना से अपनी कार्रवाई तुरंत वापस लेने की मांग की। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने नेताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। आस्ट्रेलिया ने भी म्यांमार में बने हालात पर चिंता जताई है। देश के विदेश मंत्री मारिस पेन ने सेना को कानून के शासन का सम्मान करने और गलत तरीके से हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनी गई नेशनल असेंबली के शांति से गठन का मजबूती से समर्थन करता है।

2011 तक देश में सेना का शासन रहा

म्यांमार में 2011 तक सेना का शासन रहा है। आंग सान सू की ने कई साल तक देश में लोकतंत्र लाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्हें लंबे वक्त तक घर में नजरबंद रहना पड़ा। लोकतंत्र आने के बाद संसद में सेना के प्रतिनिधियों के लिए तय कोटा रखा गया। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि सू की कभी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकतीं।

कोरोना दुनिया में: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का एक मरीज मिला, 20 लाख लोग 5 दिन तक लॉकडाउन में रहेंगे

सिडनी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होटल के एक सिक्योरिटी स्टाफ के संक्रमित मिलने के बाद 5 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पर्थ मेट्रोपोलिटन एरिया और साउथ वेस्ट रीजन में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस एरिया में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगोवन ने ऐलान किया कि लोग सिर्फ जरूरी खरीदारी, मेडिकल, एक्सरसाइज या ऐसे जॉब के लिए ही निकल सकेंगे, जिन्हें घर से नहीं किया जा सकता।

स्कूल, ज्यादातर बिजनेस, इंटरटेनमेंट वेन्यू और धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। खबर के मुताबिक, मैकगोवन ने कहा कि यह बहुत गंभीर स्थिति है। हम में से हर एक को कम्यूनिटी में वायरस फैलने से रोकने के लिए कोशिश करनी होगी। लॉकडाउन वाले इलाकों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर राज्य की राजधानी पर्थ में रहते हैं।

क्वारैंटाइन सेंटर बनाए गए होटल में तैनात था गार्ड

पॉजिटिव पाया गया शख्स एक होटल की सिक्योरिटी में तैनात था। इस होटल को क्वारैंटाइन फैसिलिटी बनाया गया है। यहां कोरोना के 4 मरीज एडमिट थे। इनमें से 2 ब्रिटेन में मिले नए वैरिएंट और 1 साउथ अफ्रीका में मिले स्ट्रेन से संक्रमित है। ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं।

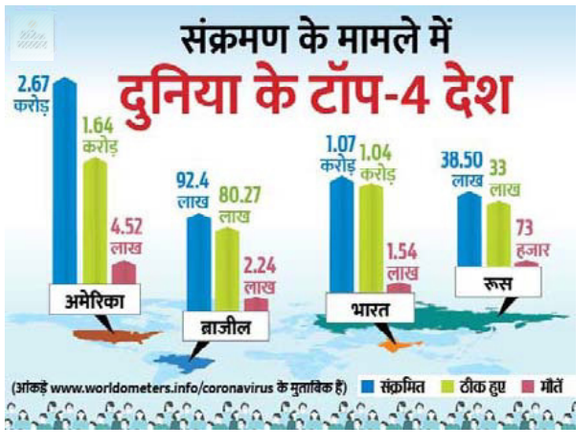

इस गार्ड ने 26 और 27 जनवरी को 12-12 घंटे की शिफ्ट की। जिस फ्लोर पर वह तैनात था, वहां ब्रिटेन के वैरिएंट

से संक्रमित मरीज थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गार्ड में भी यह संक्रमण हो सकता है।

27 लाख आबादी वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोरोना काबू में है। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, यहां महामारी शुरू होने के बाद से महज 902 केस मिले हैं। अभी सिर्फ 12 एक्टिव केस हैं। 800 से ज्यादा केस दूसरे देशों से लौटे थे। सिर्फ 100 लोकल लोग वायरस से संक्रमित हुए। पूरे आस्ट्रेलिया में अब तक 28,818 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें 909 की मौत हुई है।

साढ़े 7 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.35 करोड़ से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 37 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

एस्ट्राजेनेका यूरोपियन यूनियन में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाएगी

यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सला वोन डेर ने कहा है कि फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने उन्हें यूरोपियन यूनियन के लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने का भरोसा दिया है। यह कंपनी साल के पहले 4 महीनों में एक्स्ट्रा 90 लाख डोज सप्लाई करेगी। इस दौरान कंपनी कुल 4 करोड़ डोज देगी। यह सप्लाई तय समय से एक सप्ताह पहले शुरू की जाएगी। वैक्सीनेशन में देरी की वजह से यूरोपियन कमीशन पहले ही आलोचना झेल चुका है।

कोरोना से लड़ाई के लिए 3 करोड़ पाउंड जुटाने वाले बुजुर्ग संक्रमित

100 साल के कैप्टन टॉम मूर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन मूर ने पिछले साल नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए लाखों पाउंड जुटाए थे। इसके बाद से उन्हें हीरो की तरह देखा जाने लगा। मूर की बेटी ने बताया कि पिछले सप्ताह उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

लोकल मीडिया के मुताबिक, निमोनिया का इलाज चलने की वजह से अब तक मूर को वैक्सीनेट नहीं किया गया था। पिछले अप्रैल में 100 साल के होने वाले मूर ने ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए 3.20 करोड़ पाउंड से ज्यादा जुटाए थे। इसके लिए जुलाई में देश की क्वीन ने उनका सम्मान भी किया था।

हांगकांग के लोगों के लिए ब्रिटेन का नागरिक बनने का रास्ता खुला, गुस्से से लाल हुआ चीन

लंदन। हांगकांग के रहने वालों के लिये ब्रिटेन ने नए वीजा के रास्ते खोल दिए हैं। इस तरह से अब उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता पाने में आसानी होगी। हांगकांग के करीब तीन लाख लोगों के वीजा के लिये आवेदन करने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है, जब चीन और हांगकांग दोनों ही कह चुके हैं कि वे 31 जनवरी के बाद से ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज (बीएनओ) वीजा को हांगकांग की यात्रा करने का वैध दस्तावेज नहीं मानेंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब हमारी हांगकांग के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके 1997 में हांगकांग को सौंपे जाने की शर्तों का चीन ने उल्लंघन किया है। शर्तों के तहत ही करीब 23 साल पहले हांगकांग को चीनी अधिकारियों को सौंपा गया था।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि हम हांगकांग के लोगों के ब्रिटेन में काम करने और हमारे देश में अपना घर बनाने के लिए नई वीजा व्यवस्था लेकर आए हैं। ऐसा करके हमने इतिहास के अपने गहरे संबंधों और हांगकांग के लोगों के साथ अपनी दोस्ती का सम्मान किया है। इस व्यवस्था के तहत बीएन(ओ) दर्जा प्राप्त लोग और उनके परिवार के सदस्य ब्रिटेन में रहने, पढ़ने और काम करने के लिए आ सकेंगे। जैसा कि अन्य वीजा में होता है। ब्रिटेन में पांच साल रहने के बाद वे यहां बसने के लिए आवेदन कर पाते हैं और उसके बाद 12 और महीनों के इंतजार के बाद ब्रिटिश नागरिकता के लिये आवेदन कर पाते हैं।

इसकी प्रतिक्रिया में चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल में कहा था कि वह अब बीएन(ओ) पासपोर्ट को वैध यात्रा दस्तावेज के तौर पर मान्यता नहीं देता। चीन का कहना है कि हांगकांग में मार्च 2019 में जैसे प्रदर्शन हुए उन्हें रोकने के लिये नया सुरक्षा कानून जरूरी है। इस कानून को लेकर हालांकि दुनियाभर में प्रतिक्रियाएं हुई और विरोधी इसे चीन के अर्धस्वायत्त क्षेत्र के तौर पर हांगकांग की क्षेत्रीय स्वतंत्रता को कुचलने वाला करार दे रहे हैं।

ट्रम्प को लेकर नया खुलासा: पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थक हिंसक गुटों से जांच एजेंसियों का ध्यान मोड़ा

वाशिंगटन अमेरिका में पिछले साल जब रंगभेद विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीतने के लिए किसी फॉर्मूले की तलाश कर रहे थे। उस समय जांच एजेंसियों की नजर धुर दक्षिणपंथी गुटों पर थी। लेकिन, ट्रम्प ने बार-बार जोर दिया कि देश को उग्र वामपंथी संगठनों से खतरा है। अटॉर्नी जनरल और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने फौरन अपनी प्राथमिकताएं बदल दीं। उधर, ट्रम्प ने खुलकर असंतोष और गुस्से को हवा देना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा संसद भवन-कैपिटल बिल्डिंग पर दक्षिणपंथी उग्रवादियों के हमले में हुआ। वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रम्प के निर्देशों की वजह से कानूनी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने एंटीफा संगठन और अन्य वाम गुटों के खिलाफ छानबीन तेज कर दी थी।

न्याय विभाग ने चिंता जताई थी

अश्वेतों पर अन्याय के विरोध में प्रदर्शन तेज होने के बीच न्याय विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के जांचकर्ताओं और एफबीआई एजेंटों को गोरों की श्रेष्ठता के हिमायती हिंसक गुटों से फोकस हटाकर एंटिफा आंदोलन की ओर कर दिया था। न्याय विभाग के एक प्रॉसीक्यूटर ने एंटीफा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर चिंता जताई थी।

साजिश का पर्दाफाश करने का दबाव था

विभाग के इंस्पेक्टर जनरल माइकेल होरोविट्ज ने अपने साथियों को बताया कि इसमें राजनीति की भूमिका हो सकती है। घरेलू आतंकवाद से निपटने के अभियान से जुड़े न्याय विभाग के दो अधिकारियों ने बताया कि प्रॉसीक्यूटरों और एजेंटों पर वामपंथी उग्रपंथियों की आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करने का दबाव था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।

वैसे, एफबीआई में राष्ट्रपति से जुड़े श्वेत श्रेष्ठतावादियों और दक्षिणपंथी समूहों के खतरे, घरेलू आतंकवाद पर चिंता बढ़ रही थी। ट्रम्प के कहने पर अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने एंटीफा और वाम संगठनों से बड़े खतरे को फौरन मान लिया। 2019 में पद संभालने के बाद बर ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर साप्ताहिक बैठकों ने एफबीआई से पूछना शुरू किया कि वह एंटिफा से निपटने के लिए क्या कर रही है। इन बैठकों में शामिल होने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी मानते थे कि बर बढ़ा-चढ़ाकर खतरा बता रहे हैं।

उन्होंने, बर से यह भी कहा कि एंटीफा आतंकी संगठन नहीं है। जांचकर्ताओं पर एंटीफा के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रचने के सबूत जुटाने का दबाव था।

काबुल में ईडी ब्लास्ट,मौत के साए से गुजरती लोगों की जिंदगी

काबुल। अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार की सुबह भयानक विस्फोट हुआ है। काबुल के पीडी 10 इलाके में शहीद गोल चक्कर के पास विस्फोट हुआ। इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि एक चुंबकीय आईईडी ब्लास्ट ने एक वाहन को निशाना बनाया। ऐसे में पुलिस के अनुसार, इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। लोगों विस्फोट वाली जगह से सुरक्षित स्थान की तरफ कूच कर रहे हैं।

अफगानिस्तान में धमाका

लगातार धमाके-विस्फोटों से दहलाना तो अब जैसे अफगानिस्तान के लिए आम बात हो गई है। हर दिन यहां के लोग खौफ के साए में रहते हैं। ऐसे में बीते दिन भी अफगानिस्तान में धमाका हुआ था। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। चारों तरफ लोगों की चीख-पुकार से देश में मातम छाया हुआ था।

बीते दिन हुए धमाकों की पुष्टि अफगान अधिकारियों ने की है। वहीं

अफगान सैन्य कर्मियों ने घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया था। बता दें, इससे पहले शनिवार को सुबह नंगरहार प्रांत के शिरजाद जिले में अफगान सैन्य अड्डे पर हमला हुआ। जिसमें कार बम विस्फोट में आठ सैनिकों को मौत हो गई।

12 लोगों की मौत

बम धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है। ऐसे में सशस्त्र समूह के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस कार बम धमाके में 50 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है जबकि कई घायल हो गए हैं, लेकिन इस समूह द्वारा इन मौतों के बारे में अभी पुष्टी नहीं की जा सकी है। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि इससे पहले 27 जनवरी 2021 को भी राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ था। इस बीच पश्चिमी हिस्से में गोलाय दवाखाना क्षेत्र में हमला हुआ था। इस धमाके में दो लोग जख्मी हो गए थे। सूत्रों से सामने आई जानकारी में बताया कि यह विस्फोट एक वाहन में किया गया था।

रूस में नवलनी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर फिर उमड़ा जनसैलाब, हिरासत में 5000 लोग

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के धुर विरोधी एलेक्सेई नवलनी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे रूस में फिर एक बार सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। जगह-जगह प्रदर्शन हुए। पुलिस ने नवलनी की पत्नी, उनकी प्रवक्ता सहित 5000 से ज्यादा समर्थकों को हिरासत में लिया है। नवलनी की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार दूसरे सप्ताह इस भी रूस के कई शहरों में विरोध में प्रदर्शन किए गए। पुलिस की कठोर कार्रवाई का भी प्रदर्शनकारियों में कोई भय नहीं दिखा। राजधानी मास्को में प्रदर्शन रोकने के लिए सिक्योरिटी लॉकडाउन कर दिया गया था। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। मॉल और बाजारों को भी बंद करा दिया गया था। इन सभी सुरक्षा प्रबंधों के बीच मास्को में प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। नवलनी जहां बंद किए गए हैं, उस जेल की तरफ प्रदर्शनकारियों का एक दल बढ़ने लगा। यहां अफरातफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने राजधानी मास्को से ही दो हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इनमें नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनी और उनकी प्रवक्ता कीरा यार्मयूश भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या पचास हजार से ज्यादा थी। रूस के अन्य शहरों में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ओवीडी-इंफो के मुताबिक कुल 4,700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। रूस के साइबेरिया और सुदूर पूर्वी क्षेत्र के कई शहरों में भी प्रदर्शन किए गए। व्लाडीवोस्टक में बड़ी रैली निकाली गई।

कोरोना संक्रमित मां भी बच्चों को पिला सकती हैं दूध : डॉक्टर स्वाति तोमर

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इन दिनों कोरोना संक्रमित केसों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में कुछ लोग अब लापरवाही करने लगे हैं, जिससे संक्रमण का डर अधिक हो रहा है। एम्स की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति तोमर ने बताया कि बहुत से लोगों में यह संदेह रहता है कि क्या कोरोना सक्रमित महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को दूध पिला सकती हैं या नहीं। ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मां अपने बच्चे को दूध पिता सकती है। इससे बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।

डॉक्टर स्वाति तोमर ने बताया कि इन दिनों गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें अपने खाने पीने का समय हमेशा ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्हें पौष्टिक भोजन लेना होगा। इसमें इन दिनों ताजा सब्जियों के साथ-साथ हरा साग और अन्य हरी सब्जियां खानी होंगी। वहीं, ताजा फलों का घर में निकला जूस पीना चाहिए। खासतौर से संतरा और मौसमी इसमें शामिल हो, जिससे शरीर को विटामिन सी मिल सकता है। वहीं, गर्भवती महिलाओं को इन दिनों डरना नहीं चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जितना खतरा कोविड से आम महिलाओं को होता है। उतना ही खतरा गर्भवती महिलाओं को भी होता है। हालांकि 40 से ज्यादा उम्र की गर्भवती महिलाओं को और अन्य बीमारियों से ग्रस्त महिलाओं को खतरा अधिक होगा। इसके लिए उन्हें साफ-सफाई पर भी विशेष जोर देना होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना के टीकाकरण के दिशा-निर्देशों में गर्भवती महिलाएं भी टीकाकरण करा सकती हैं।

पांचवें सीरो सर्वे में 56.13 फीसद लोगों में पाई गई एंटीबॉडी: सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि पांचवे सीरो सर्वे में 56.13 फीसद लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने कहा कि 28,000 लोगों के सैंपल लेकर जांच की गई। हर वार्ड से 100 सैंपल लिए गए। उत्तरी दिल्ली में सबसे कम 49.09 फीसद लोगों में एंटीबॉडी पाई गई।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम हैं और अस्पताल में कोरोना के मरीज़ भी कम भर्ती हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप मास्क जरूर लगा के रखे। अभी आपको कुछ दिन और मास्क लगाने की जरूरत है और शारीरिक दूरी का भी पालन की करने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि 56.13 फीसद लोगों में एंटीबॉडी मिलने का मतलब आधी से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। डाक्टर कहते हैं कि दिल्ली के लोगों में अब हर्ड इम्युनिटी बन गई है। यही वजह है कि सब कुछ काफी हद तक सामान्य होने के बावजूद कोरोना का संक्रमण न के बराबर है। बता दें कि पांचवें सीरो सर्वे के लिए 11 से 22 जनवरी के बीच दिल्ली के सभी वार्डों से करीब 28 हजार लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। यह अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है। पहले सीरो सर्वे में करीब 23 फीसद, दूसरे सीरो सर्वे में करीब 29 फीसद , तीसरे व चौथे सीरो सर्वे में करीब 25 फीसद लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी।

सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जल्द खुलेंगे स्कूल; शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हाई स्कूल और इंटर के स्कूल खुलने के बाद अब नर्सरी के स्कूल को भी खोलने की प्रक्रिया शुरु होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हम जल्द ही नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं । इस बार कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी देर हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाकी की कक्षाएं भी खुलेंगी। सीएम केजरीवाल ने निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से बातचीत करते हुए ये बातें कही।

केजरीवाल ने कहा कि बच्चों के परिजनों की सहमति से बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। यह वैकल्पिक होगा। यानी किसी को जबरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर व्यक्ति चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, उसका सपना होता है कि उसके बच्चें अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। दिल्ली सरकार का यह लक्ष्य है कि वह दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करे, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट विद्यालय पहले से ही शानदार हैं। यही कारण है कि भारत के 200 सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट स्कूलों में 100 स्कूल दिल्ली के है। हमने पिछले 5-6 वर्षों में बदहाल पड़े सरकारी स्कूलों को सुधारा है और उन्हें प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाने का प्रयास किया है। दिल्ली सरकार के लिए प्राइवेट विद्यालय भी प्राथमिकता रखते हैं।

सरकारी और प्राइवेट स्कूल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की दो बांहे है और इन्हें साथ में काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल साथ काम करके पूरे विश्व के लिए बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का उदाहरण बने, ठीक उसी तरह अब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी साथ काम करने की जरूरत है। सरकारी और प्राइवेट विद्यालय एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार प्राइवेट विद्यालयों के स्वायत्तता की सख्त हिमायती है, लेकिन हम किसी भी बच्चें और उनके अभिभावकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नही होने देंगे। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आदेश भी दिया।

बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बिना किसी तैयारी और प्रशिक्षण के कोरोना महामारी के दौरान अपने प्रयासों से शिक्षा में होने वाले नुकसान को कम करने लिए प्राइवेट विद्यालयों को धन्यवाद किया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों के लिए विश्व स्तर के करिकुलम बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को साथ मिल कर काम करना होगा, ताकि दिल्ली के सभी बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा एलान, छह फरवरी को देश भर में करेंगे चक्काजाम

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने छह फरवरी को 12 से तीन बजे तक चक्का जाम करने की घोषणा की है। इस दौरान सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद रहेंगे। मोर्चा ने किसान नेताओं व मोर्चा के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मोर्चे के नेताओं का आरोप है कि आंदोलन स्थल की बिजली, पानी काटी जा रही है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, शौचालयों की संख्या घटाई जा रही है। आवागमन के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ताकि आंदोलन को दबाया जा सके।संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कुंडली बार्डर पर बैठक कर रणनीति बनाई। किसान नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, डा. दर्शनपाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, प्रेम सिंह भंगू, परमेंद्र मान आदि ने बताया कि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में चक्का जाम किया जा रहा है। आरोप लगाया कि लगातार युवाओं से मारपीट हो रही है। 26 जनवरी को जो वाहन जब्त किए गए हैं, इनके बारे में कोई अता-पता नहीं दिया जा रहा है। सरकार सड़कें खोदने के साथ गलियों के भी रास्ते बंद कर रही है। किसान नेताओं ने कहा कि ऐसे माहौल में सरकार से बातचीत का कोई औचित्य नहीं बनता है।

किसान नेताओं ने कहा कि ट्रैक्टर परेड के बाद से अभी तक कई लोग लापता हैं। अब तक उनके पास जो आधिकारिक जानकारी आई है, उसमें 122 लोगों के विभिन्न थानों में होने की बात कही गई है और 43 लोग जेल में हैं। दिल्ली और आसपास में किसान आंदोलन का 68 दिन हो चुका है। यूपी गेट पर धरना दे रहे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए अलग से बजट और कृषि ऋण को माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना भी सरकार को लानी चाहिए। बजट से निराशा जताई। कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी सरकार दे, इसके बाद ही वह धरना समाप्त करेंगे। वह वार्ता के लिए तैयार हैं और नए सिरे से होनी चाहिए। दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है।

चोरों के आगे बेबस हुई दिल्ली पुलिस, 24 घंटे में चार एटीएम से चोरों ने उड़ाए 50 लाख रुपये

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिले में 24 घंटे में चोरों ने ताबड़तोड़ चार एटीएम काटकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। इनमें से तीन एटीएम से बदमाश 50 लाख से ज्यादा रुपये चोरी कर ले गए हैं। हालांकि, एक एटीएम से बदमाश पुलिस गश्त के चलते रुपये ले जाने में सफल नहीं हो सके। सभी घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की एक दर्जन टीमों को लगाया गया है। जानकारी के अनुसार महिंद्रा स्कार्पियो सवार चार युवकों ने शनिवार तड़के न्यू फ्रेंड्स कालोनी स्थित आइडीबीआइ बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश ट्रे चोरी कर ली। बैंक अधिकारियों के मुताबिक इस एटीएम में उस समय करीब 10 लाख रुपये थे। वारदात से पहले आरोपितों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर काले रंग का पेंट स्प्रे कर दिया था। इसके बाद 24 घंटे के

रविवार को ही तड़के सरिता विहार के जसोला स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम को भी काटने का प्रयास किया गया, हालांकि यहां से बदमाश रुपये ले जाने में सफल नहीं हुए।

भीतर ही रविवार को तड़के बदमाशों ने ओखला थाना क्षेत्र के तेहखंड स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम को गैस कटर से काट दिया। यहां से करीब 25 लाख रुपये चोरी कर लिए। इसके कुछ ही देर बाद सनलाइट कालोनी के भगवान नगर में आइसीआइसीआइ बैंक के एटीएम को भी गैसकटर से काटकर करीब 19 लाख रुपये उड़ा लिए। यही नहीं रविवार को ही तड़के सरिता विहार के जसोला स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम को भी काटने का प्रयास किया गया, हालांकि यहां से बदमाश रुपये ले जाने में सफल नहीं हुए। ओखला के तेहखंड गांव निवासी पम्मी ने बताया कि उनके घर के भूतल में पिछले दो साल से एटीएम लगा है। स्कार्पियो सवार आरोपितों ने घटना से एक दिन पहले भी एटीएम के सामने गाड़ी लगाकर रेकी की थी। उस समय उन्हें लगा कि आरोपित वाहन चोर हैं। इसकी शिकायत भी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शनिवार को तड़के बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पम्मी ने बताया कि रात दो बजे के बाद से एटीएम का सायरन बजने लगा था। इसकी आवाज उन्हें भी सुनाई दी, लेकिन उन्हें लगा कि पूर्व की तरह सायरन कुछ देर में बंद हो जाएगा। दरअसल पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सायरन खुद ही बजने के बाद बंद हो गया था। सुबह उनके परिवार के सदस्य बाहर निकले तो उन्होंने एटीएम कटा हुआ देखकर पुलिस को सूचना दी। ओखला, एनएफसी और सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्रों में एटीएम में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस की एक दर्जन से अधिक टीमें चोरों की तलाश में जुटी हैं। आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सेना को समृद्ध और सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाएगा बजट, रक्षा विशेषज्ञों ने सराहा

नई दिल्ली। संवेदनशीलता को देखते हुए भले ही केंद्रीय बजट में खुले तौर पर रक्षा क्षेत्र को लेकर किए गए प्रविधान की चर्चा नहीं की गई, लेकिन इसमें बढ़ोतरी करने व सैनिक स्कूलों को खोलने की घोषणा को सेवानिवृत्त व सेवारत सैन्य अधिकारियों ने सराहा है। उनका कहना है कि यह बजट सेना को समृद्ध और सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाएगा।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने कहा कि सेना को समृद्ध बनाने की दृष्टि से सरकार ने बेहतरीन बजट पेश किया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 1.39 फीसद बजट बढ़ाया गया है, जोकि अच्छा कदम है। यह बजट देश को सामरिक दृष्टि से भी काफी मजबूत बनाने वाला है। वहीं, प्रमोद के. सहगल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में किया गया प्रविधान कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत थी। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोलने का फैसला सराहनीय है। मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ध्रुव कटोच का कहना है कि बजट ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। कम बजट में हम कैसे बेहतर निर्णय करके उसका इस्तेमाल करते हैं, यह जरूरी है। रक्षा बजट को बढ़ाना है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा। साथ ही हमें अपने आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करना होगा। कर्नल आरएस डूडी ने कहा कि सैनिक स्कूल खोलने का फैसला स्वीकार योग्य है। इससे निश्चित तौर पर भावी पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और सेना को अच्छे अफसर मिल सकेंगे। इसके अलावा बजट में किए गए अन्य प्रविधान भी सेना को मजबूत करेंगे।

बैरिकेडिंग को मजबूत करने पर सवाल उठाने वालों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया जवाब

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर धरना-प्रदर्शन के दौरान नया नारा दिया है- %कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं%। दरअसल, यूपी गेट पर 28 नवंबर से चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन में सोमवार को आंदोलनकारियों की भारी भीड़ रही। इस मौके पर राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 18 माह कृषि कानून स्थगित करने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि तीनों कानून वापस हो और एमएसपी की की गारंटी मिले तभी किसान उठेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अक्टूबर तक भी

खत्म नहीं होगा। इस बीच मंगलवार को शिवसेना के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने यूपी गेट पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वह भीड़ ज्यादा होने के चलते मंच पर नहीं जा सके। इससे पहले पहुंचे कई नेताओं ने मंच साझा किया है और अपनी बात रखी है। वहीं, इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि अगर विपक्ष हमारा समर्थन करने के लिए आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर नेता आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। आंदोलन को किसानों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया गया है, यह पुलिस बैरिकेडिंग के कारण है। दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या में इजाफा होने के चलते कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बीच समाजसेवा मेधा पाटकर भी यूपी गेट पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंच हैं। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिंघू, टिकरी और गाज़ीपुर सीमाओं के आसपास और 26 जनवरी के बाद या बाद में कथित रूप से अवैध हिरासत में रखे गए किसानों सहित सभी लोगों को रिहा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। इसी के साथ यहां पर सीमेंट के बैरिकेड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं। जिससे अगर कोई किसान ट्रैक्टर के जरिये आगे बढ़े तो उसके टायर फट जाएं या फिर पंचर हो जाएं। सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना-प्रदर्शन के चलते दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार को भी रूट डायवर्जन किया गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं, जिससे यात्रा सुगम की जा सकती है। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तारों के साथ नुकीली कीलें भी लगाई गई हैं, जिससे किसान प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची। इसे रेवाड़ी के रास्ते मुंबई के लिए रवाना किया गया। श्रीगंगानगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में रोक दिया गया। इसे लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि एक हजार से ज्यादा किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पंजाब मेल के मार्ग में बदलाव कर दिया गया।

राहुल गांधी बोले सरकार किसानों से बातचीत के लिए पुल बनवाए दीवार नहीं

नई दिल्ली। किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। उधर 26 जनवरी के दिन राजधानी की सड़कों और लाल किले पर उपद्रवियों ने जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। देश दुनिया में उपद्रवियों के इस कृत्य की निंदा और आलोचना की गई। इसके कारण कुछ किसान संगठन आंदोलन से अलग भी हो गए, उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सम्मान के साथ वो किसी तरह का खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पर ऐसा काम किया उन्होंने ऐसा करके किसानों को शर्मसार किया है इससे दुखी होकर वो आंदोलन खत्म कर रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से यूपी गेट(गाजीपुर बॉर्डर) पर पुलिस की सुरक्षा की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा है कि पुल बनाए जाएं दीवार नहीं। इसका मतलब वो

सरकार से कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए पुल बनाए ना कि दीवार बनाकर सारे रास्ते बंद कर दे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी चार तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस को लगा था कि कुछ और भी जगहों से किसान उठ जाएंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। यूपी गेट पर ही आंदोलन खत्म होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, काफी संख्या में 27 जनवरी को किसान यहां से उठकर चले गए थे। यहां लगाए गए टेंट भी उखड़ने लगे थे, लंगर के लिए रखे गए बर्तन आदि उठाए जा रहे थे, काफी संख्या में पुलिस के पहुंचने के बाद यहां बैठे किसानों के मन में भी भय था। देर शाम तक आंदोलन स्थल खाली हो जाने की बातें कही जाने लगी थी मगर अचानक से एक अफवाह के बाद हालात बदल गए। अब यहां फिर से किसानों और अन्य चीजों की संख्या बढ़ गई है। अब दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए अपने सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता कर दिया है। यूपी गेट, टिकरी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सड़कों को खोदकर कीलें लगा दी गई हैं। लोहे और सीमेटेंड जर्सी बैरियर के ढेर लगा दिए गए हैं। कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि किसी तरह से आंदोलन में बैठे किसान दिल्ली की ओर जाने की मन भी बनाए तो उनको पूरा दिन इन बैरिकेड को हटाने में ही लग जाएगा फिर भी वो उसे हटा नहीं पाएंगे। अब टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वहां भी ऐसे ही इस्तेमाल किए हैं। सड़कें खोद दी गई हैं, सड़क पर कीलें लगा दी गई हैं। सीमेंटेड बैरियरों की संख्या बढ़ा दी गई है।

जल बोर्ड में हुए घोटाले के पैसे से दूसरे प्रदेश में राजनैतिक विस्तार कर रही आप : आदेश गुप्ता

पश्चिमी दिल्ली। जल बोर्ड में कथित घोटाले को लेकर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नारायणा में आयोजित पदयात्रा के दौरान दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता टैक्स विकास कार्यों के लिए देती है, लेकिन आज उन पैसों का उपयोग आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक विस्तार के लिए कर रही है। जबतक जल बोर्ड के एक-एक पैसों का हिसाब नहीं दिया जाता तबतक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पदयात्रा के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करने की बात कह सत्ता में आए थे, लेकिन आज वह ईमानदारी कहां चली गई। जल बोर्ड में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा हैं और इसी कारण उनके विधानसभा क्षेत्र से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। दिल्ली सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे या नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता तक हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी। आज नारायणा से लेकर टोडापुर के लोगों तक हमारी आवाज पहुंची और उनके दिल में यह घोटाला अंकित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैनर पोस्टर लगाने वाली कंपनियों को मुख्यमंत्री कार्यालय से धमकी दी जाती है कि अगर जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का बैनर पोस्टर लगाया तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। भाजपा यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा आरोप गलत है तो मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आएं और हिसाब देकर जनता को बताएं कि भाजपा जो आरोप लगा रही है वह गलत है। उनका कहना है कि इस मसले पर दिल्ली सरकार की चुप्पी साफ जाहिर करती है कि जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड पूरी तरह कंगाल, बेहाल और बदहाल हो गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने वाला है बजट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर अधिवक्ताओं के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अधिवक्ताओं ने बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मजबूत कदम और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रविधान को भविष्य में बदलाव की नींव रखने वाला बताया। वहीं, कुछ बजट से खासे संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। उनके हिसाब से बजट में निम्न व मध्यम वर्ग को राहत नहीं दी गई, जिसके कारण उनके लिए आना वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेरे हिसाब से इस बार का बजट ठीक है। स्वदेशी को अपनाने पर जोर देने की बात की गई है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एनआरआइ को भारत में निवेश करने की सुविधा दी गई है। इससे रोजगार में वृद्धि होगी। 75 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को आयकर रिटर्न में छूट दी गई है, जो बहुत बढ़िया कदम है। इससे हमारे बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बाद सरकार देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो कुछ कर सकती थी, वह बजट में करने की कोशिश की गई है। विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कई अहम प्रविधान बजट में किए हैं, जो सराहनीय हैं। कोरोना से सामने आई स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अच्छा बजट पेश किया है। निश्चित तौर पर यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की नींव रखेगा। जहां तक अधिवक्ताओं की बात है तो इस बजट में महामारी के बाद से आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं के लिए निराश करने वाला बजट है। न ही उनके लिए कोई प्रविधान किया गया और न ही कर में कोई छूट देकर राहत दी गई। कोरोना महामारी के बीच पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे वक्त में शिक्षा व पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का असर आम आदमी पर पड़ेगा। इस बजट से निम्न और मध्यम वर्ग को खासी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार राहत देने में नाकाम रही है।

एम्स में चार फरवरी से सामान्य होगी ओपीडी सेवा

नई दिल्ली। कोरोना का खौफ खत्म चुका है। इसलिए अब अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी सामान्य होने लगी हैं। इसी क्रम में एम्स में करीब साढ़े दस माह बाद चार फरवरी से ओपीडी सेवा पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। इसलिए सभी विभागों की ओपीडी में प्रतिदिन नए पुराने 150 मरीज देखे जाएंगे।

इसलिए अब मरीजों को एम्स में इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। खास बात यह है कि ओपीडी में इलाज के लिए ऑनलाइन अप्वइंटमेंट की बाध्यता भी नहीं रहेगी। इसलिए बगैर अप्वाइंटमेंट के भी एम्स की ओपीडी में पहुंचने पर इलाज हो सकेगा। इससे दिल्ली सहित देश भर से एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण पिछले साल 18 मार्च से एम्स में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। बाद में 25 जून को एम्स ने कुछ प्रतिबंधों के

ओपीडी में इलाज के लिए ऑनलाइन अप्वइंटमेंट की बाध्यता भी नहीं रहेगी। इसलिए बगैर अप्वाइंटमेंट के भी एम्स की ओपीडी में पहुंचने पर इलाज हो सकेगा। इससे दिल्ली सहित देश भर से एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

साथ ओपीडी शुरू हुई। शुरुआत में सभी विभागों में 15-15 मरीज देखे जा रहे थे।

बाद में ओपीडी में सभी विभागों के लिए मरीजों की संख्या बढ़ाकर 30 निर्धारित की गई। पिछले कुछ दिनों से ओपीडी में मरीजों की संख्या और भी बढ़ गई है। लेकिन अभी सिर्फ आनलाइन व टेलीफोन पर अप्वाइंटमेंट लेने वाले मरीज ही देखे जा रह हैं। इससे मरीजों को परेशानी भी हो रही है। कोरोना की संक्रमण दर भी ना के बराबर रह गई है। लिहाजा, एक फरवरी को एम्स प्रशासन ने ओपीडी को पूरी तरह सामान्य करने का आदेश जारी किया है। संस्थान के सभी कर्मचारियों को भी पहले की तरह तय समय पर ड्यूटी आने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा सभी विभागों में प्रतिदिन 50 या कोरोना काल से पहले की तरह निर्धारित संख्या में नए मरीज देखे जाएंगे।

वहीं सभी विभागों में 100 पुराने मरीज देखे जाएंगे। ओपीडी में 20 फीसद मरीज बगैर अप्वाइंटमेंट के देखे जाएंगे। जबकि करीब 70 फीसद मरीज अप्वाइंटमेंट के आधार पर ही देखे जाएंगे। 10 फीसद मरीज ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है। ओपीडी में इलाज के लिए अधिक से अधिक एक माह के अंदर का समय मिल सकेगा। एक माह से अधिक वेटिंग होने पर आनलाइन इलाज के लिए समय नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में बगैर अप्वाइंटमेंट के भी एम्स पहुंचकर मरीज इलाज करा पाएंगे।

संपादकीय

अमेरिका में भरोसे की नई भोर

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन का शपथ लेना इसके इतिहास के एक सबसे दुखद और काले अध्याय का अंत होने के साथ ही उम्मीद व भरोसे से भरे एक नए युग की शुरुआत भी है। पूर्व उप-राष्ट्रपति और पूर्व सीनेटर बाइडन के राष्ट्रपति पद संभालते ही न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई सुबह तय है। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवृत्ति किस कदर विनाशकारी रही, इसे देश-दुनिया के तमाम मीडिया ने बताया ही है। ह्वाइट हाउस में बिताए गए उनके चार वर्षों में कई बड़े रद्दोबदल हुए। मसलन, नस्ल संबंधी मसलों के खिलाफ अमेरिका ने जो लाभ कमाया था, ट्रंप ने उनमें से ज्यादातर को गंवा दिया। आप्रवासन को उन्होंने जमकर हतोत्साहित किया, जबकि गैर-यूरोपीय देशों से आए लोगों ने ही अमेरिका का निर्माण किया है। पर्यावरण से जुड़े सौ से अधिक प्रावधान उन्होंने वापस लिए। मीडिया सहित देश के तमाम संस्थानों को उन्होंने लगातार निशाना बनाया। और तो और, पेरिस समझौते, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी वैश्विक संधियों-संस्थाओं से उन्होंने अमेरिका को निकाल बाहर किया, और विश्व नेता की उसकी छवि खंडित करके रूस व चीन जैसे देशों को उस शून्य को भरने दिया। स्थिति यह थी कि ओवल ऑफिस से विदा होते हुए भी ट्रंप ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं किया। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने के बजाय उन्होंने अपने समर्थकों को बगावत के लिए उकसाया। संक्षेप में कहें, तो अमेरिका में अलगाव की लकीर को गहरा करके उन्होंने अपना पद छोड़ा है। विभिन्न मुद्दों को निपटाने और समस्याओं के समाधान के मामले में भी ट्रंप अमेरिका के अक्षम राष्ट्रपतियों में गिने जाएंगे। कोविड-19 से निपटने का ही मामला लें, तो इस देश के पास सबसे बड़ा और अत्याधुनिक स्वास्थ्य ढांचा है। इसे तो अन्य राष्ट्रों के मुकाबले बेहतर तरीके से इस महामारी से लड़ना चाहिए था। मगर कोरोना के कुल वैश्विक मामलों में 25 फीसदी से अधिक यहीं दर्ज किए गए और कुल मौतों में भी 20 फीसदी से अधिक मौतें यहीं हुईं, जबकि यहां वैश्विक आबादी का महज पांच फीसदी हिस्सा ही बसता है। सुखद है कि अब अमेरिका की कमान एक ऐसे नेता के हाथों में है, जो देश को इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकालने में सक्षम हैं। अपने चुनाव अभियान में बाइडन ने मतदाताओं से वायदा भी किया था कि वह सिर्फ अपने समर्थकों के मुखिया के रूप में नहीं, पूरे राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जीत के बाद उनके यही शब्द थे कि वह समाज में बढ़ती अलगाव की भावना को कम करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, सुकून की बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे इंसान ने सत्ता संभाली है, जो अमेरिकी संस्थानों में विश्वास रखता है, फिर चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो या फिर मीडिया। तथाकथित 'कंजर्वेटिव' राष्ट्रपतियों के विपरीत, बाइडन तमाम परंपराओं का सम्मान करते रहे हैं। पिछले चार वर्षों में ह्वाइट हाउस ने 'जवाबदेही-मुक्त क्षेत्र' के रूप में काम किया है। बाइडन ने स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार में वह हर तरह से जवाबदेह बनेगा। नए प्रशासन से उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि विभिन्न विभागों व एजेंसियों के शीर्ष पदों को भरने में विविधता, विषय-वस्तु की विशेषज्ञता और क्षमता का पूरा ख्याल रखा गया है। माना जा रहा है कि नया प्रशासन जिम्मेदारी संभालते ही कोरोना वायरस सुधार पैकेज तो जारी करेगा ही, ऐसे कई आदेश भी पारित करेगा, जो ट्रंप के कई विवादित फैसलों को पलट देगा। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा बनने और मुस्लिम देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को रद्द करने जैसे कदम इनमें प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं।

नई सरकार कोरोना वायरस को लेकर भी कई नियम बना सकती है। जैसे मास्क पहनना अनिवार्य बनाया जा सकता है, कोविड जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, और किराया व देनदारी आदि भुगतान न कर सकने वाले लोगों की बेदखली रोकी जा सकती है। बाइडन प्रशासन कोविड-19 से युद्धस्तर पर निपटने के लिए तैयार दिख रहा है, जिसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि नए राष्ट्रपति सत्तासीन होने से पहले ही विशेषज्ञ व वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। इसी तरह, घरेलू व विदेश नीति, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टीमों के गठन में भी अनुभव और प्रतिभा को तवज्जो दी गई है। बाइडन अमेरिका को फिर से विश्व नेता बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यह वह हैसियत है, जिसको अमेरिका एक सदी से भी अधिक समय तक जीता रहा है। अपने नाटो सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ऐसी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए यह तत्पर दिख रहा है, जो दुनिया के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। निस्संदेह, बाइडन प्रशासन वैश्विक राजनीति और नीतियों में भी हलचल पैदा करेगा। नए राष्ट्रपति ने कहा भी है कि 'अमेरिका इज बैक', यानी अमेरिका लौट आया है, और हम एक बार फिर शीर्ष पर आएंगे। 32 साल पहले अपने विदाई भाषण में रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका को 'शाइनिंग सिटी ऑन अ हिल' कहा था। खुशहाल अमेरिका की कल्पना करते इस मुहावरे का इस्तेमाल उन्होंने अपने आठ वर्षों के राष्ट्रपति काल म् लगातार किया। रोनाल्ड रीगन ने, जो तब सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध में मुकाबिल थे, हमेशा अमेरिका को अच्छी ताकत के रूप में देखा था। विडंबना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने का वायदा तो किया, पर अमेरिका के इस चरित्र को 1,461 दिनों में खत्म कर दिया। रीगन जब ह्वाइट हाउस पहुंचे थे, तब बाइडन 39 वर्षीय सीनेटर थे। आज जीवन के आठवें दशक में वह एक बार फिर अमेरिका को अच्छी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं, और देश को 'शाइनिंग सिटी ऑन अ हिल' बनाना चाहते हैं।

प्रवीण कुमार सिंह

अफगान-तालिबान शांति वार्ता के मायने, भारत पर व्यापक असर की आशंका

एक और बात जो ध्यान देने योग्य है कि तालिबान कोई राज्य या उसके द्वारा स्थापित स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह शांति समझौते को पूर्ण रूप से मानेगा और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर अफगानिस्तान को अपने पुराने हालात में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अफगानिस्तान में चल रही बदलाव की प्रक्रिया का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत, अफगानिस्तान सरकार और लोकतंत्र का समर्थक रहा है तथा वहां स्थिति अच्छी हो, इसके लिए विकास के कई कार्य भी किए हैं।

अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हालांकि कई समस्याओं से घिरी इन वार्ताओं का परिणाम क्या होगा, यह कहना अभी मुश्किल है। जहां एक ओर इस शुक्रवार तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को घटा कर 2,500 किया जाना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में हो रहे सत्ता परिवर्तन पर भी दोनों पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।

दरअसल अफगानिस्तान में फिर से बढ़ रही हिंसा की घटनाओं का भी इन वार्ताओं पर व्यापक असर पड़ रहा है। एक बात और स्पष्ट है कि इस समझौते का प्रभाव न सिर्फ तालिबान, अफगानिस्तान और अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि दक्षिण एशिया से लेकर समूचे मध्य एशिया पर पड़ेगा। भारत पर इसके प्रभाव को समझने के लिए हमें दो विषयों को देखना होगा। इस समझौते में क्या है व अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाने पर क्या हो सकता है और दूसरा पाकिस्तान के साथ तालिबान के गठजोड़ की भूमिका क्या है।

गौरतलब है कि अमेरिका में वर्ष 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत अन्य कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में दो कदम उठाए। इस घटना के एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हवाई हमले शुरू किए। बाद में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम के और भी देश इसमें जुड़ गए तथा उनकी संयुक्त सेना अफगानिस्तान पहुंच गई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की संज्ञा दी और बाद के राष्ट्रपति भी इस अभियान में सक्रियता से शामिल रहे। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने पांच हजार अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा। साथ ही, उन्होंने तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिकी फौज को ज्यादा छूट भी दी। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के अनुसार करीब 19 साल से चल रहे इस युद्ध में डेढ़ लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अमेरिका ने करीब दो खरब डॉलर खर्च किए हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने लोकतांत्रिक अफगान सरकार को मजबूत करने की भी कोशिश की, लेकिन इन सबके बावजूद अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। इस समयावधि में एक बात सामने आई कि अफगानिस्तान समस्या का हल बिना पाकिस्तान पर नकेल कसे नहीं किया जा सकता। देखा गया है कि पाकिस्तान के तालिबान से अच्छे संबंध है। तालिबान के गठन में भी पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ पर तालिबान को मदद करने के आरोप भी लगे हैं। तालिबान के नेताओं के सुरक्षित ठिकानों में अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के इलाके शामिल हैं। ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो 1996 से पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था, तब भी उसके नेताओं और लड़ाकों के लिए पाकिस्तान एक सुरक्षित ठिकाना था। वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। अमेरिका की कार्रवाई के बाद तालिबान के लड़ाकों और शीर्ष नेतृत्व ने पाकिस्तान में शरण ले ली और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे।

यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश दो दशकों तक लगातार युद्ध करके और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी तालिबान को खत्म करने में नाकाम रहा और अंत में उसे तालिबान से समझौता करना पड़ा। इसमें भी उसे पाकिस्तान का सहयोग लेना पड़ा रहा है। पिछले साल 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को खत्म करने को लेकर एक समझौता हुआ। इस समझौते के लिए पहल सितंबर 2018 में की गई थी और नौ दौर की वार्ता के बाद अमेरिका व तालिबान के बीच समझौते तक बात पहुंची। इसमें दोनों पक्षों के बीच कई विषयों पर सहमति बनी। यह तय हुआ कि 135 दिनों में अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या घटा कर 8,600 तक सीमित कर देगा और इसी अनुपात में उसके अन्य सहयोगी भी अपने सैनिकों की संख्या में कमी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान को यह आश्वस्त करना होगा कि वह अफगानिस्तान में ऐसी किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं देगा, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को नुकसान हो। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा तालिबान नेताओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। पांच हजार तालिबान और दूसरे पक्ष के एक हजार बंदियों को भी छोड़ने की बात समझौते में की गई है। इस समझौते में तालिबान ने अफगानिस्तान से बात करने के लिए भी स्वीकार किया गया था। इस समझौते को अफगानिस्तान में पिछले करीब दो दशकों से चल रहे युद्ध को खत्म करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कोशिश के तौर पर देखा गया है। लेकिन क्या अमेरिका और तालिबान के बीच जो तय हुआ, वह सब संभव है, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति आए और इस समझौते का एक अच्छा भविष्य हो इसमें कई मुश्किलें हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते में अफगानिस्तान सरकार को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इस समझौते के कुछ विषयों पर स्पष्टता नहीं है। जैसे बंदियों को छोड़ने के संदर्भ में अफगानिस्तान सरकार का यह कहना है कि यह अमेरिका के अधिकार में नहीं आता। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने तालिबान से समझौता करके तालिबान को ज्यादा अहमियत दे दी है, जो कि अफगान सरकार की मुश्किलों को बढ़ाएगा। साथ ही, लोगों में यह संदेश भी जाएगा कि अमेरिकी फौज के चले जाने के बाद तालिबान ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आगे चल कर फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा भी जमा सकता है।

जानकारों का मानना है कि वर्तमान में तालिबान 19 वर्षो में सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है, उसके पास करीब 60 हजार लड़ाके हैं और अफगानिस्तान के कई जिलों में आज उसका वर्चस्व व्यापक रूप से कायम है। पिछले कुछ महीनों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनको लेकर तालिबान अमेरिका पर और अफगानिस्तान तालिबान पर आरोप लगा रहा है। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है कि तालिबान कोई राज्य या उसके द्वारा स्थापित स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह शांति समझौते को पूर्ण रूप से मानेगा और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर अफगानिस्तान को अपने पुराने हालात में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अफगानिस्तान में चल रही बदलाव की प्रक्रिया का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत, अफगानिस्तान सरकार और लोकतंत्र का समर्थक रहा है तथा वहां स्थिति अच्छी हो, इसके लिए विकास के कई कार्य भी किए हैं। बीते करीब ढाई दशकों के दौरान वहां के आधारभूत संरचना को ठीक करने में भारत ने अरबों रुपये खर्च किए हैं।

युवाओं के कौशल विकास से भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाया जा सकता है

किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कौशल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कौशल एक ऐसा साधना है, जिसके द्वारा युवाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल कार्यबल तैयार करके स्किल गैप को आसानी से भरा जा सकता है। कौशल सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय राज्य सरकारों, प्रशिक्षण भागीदारों और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आज इसी का परिणाम है कि विभिन्न कौशल संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने अपनी क्षमता एवं कुशलता का परिचय देते हुए नवाचार के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए हैं, जो भविष्य में अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। हमारे युवाओं में वह सामर्थ्य एवं हुनर है, जिसके बल पर भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाया जा सकता है। वर्ष 2030 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल होने की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होगी। इस युवा कार्यबल को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है, ताकि रोजगार के नए अवसरों में तेजी से वृद्धि की जा सके। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। कौशल हमें रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। साथ ही स्व-रोजगार के लिए भी प्रेरित करता है। इसमें वह शक्ति है, जिसके द्वारा हम भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कौशल के द्वारा युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को प्रासंगिक रहने के लिए 'स्किल, अपस्किल और रीस्किल' का मंत्र दिया था। इस मंत्र का उपयोग कर युवा दूसरों से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं।

युवाओं को नई-नई तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और जिला स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0' को पिछले साल अक्टूबर/नवंबर में कुछ अहम दिशानिर्देशों के साथ लांच किया गया। इस योजना का लक्ष्य वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। यह मांग और उद्योगों पर आधारित एक ऐसी योजना होगी, जो आधुनिक कौशल पर काम करेगी और जिला स्तर पर युवाओं को सशक्त बनाएगी। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर जॉब की पहचान की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर जिला कौशल समिति (डीएससी) का गठन किया जाएगा।

ये समितियां उद्योगों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर स्किल्स की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। विभिन्न स्थानों पर कौशल मेलों का भी आयोजन करेंगी जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बारे में अवगत कराया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट, स्वरोजगार और शिक्षुता के समान अवसर प्रदान करने में भी अपनी भागीदारी निभाएंगी। इस योजना के अंतर्गत संकल्प प्रोजेक्ट के द्वारा स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को प्रमाणित किया जाएगा और बड़े स्तर पर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इसमें राज्य कौशल विकास मिशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में 'स्किल इंडिया मिशन' की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करना था। आज इस मिशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को नवीन तकनीकों पर आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक एक करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज देश भर में 700 से अधिक जिलों में 26,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। जहां पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 48.7 करोड़ श्रमिक हैं।

आज भी हमारे देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या अधिक है, जो अपने काम में निपुण तो होते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं होते हैं। इसीलिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय संकल्प प्रोजेक्ट के द्वारा ऐसे श्रमिकों को प्रमाणित कर रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

इसके साथ ही भविष्य के कौशल निर्माण के लिए भी श्रमिकों को तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारी महत्वपूर्ण पहलों में से एक आरपीएल (रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग) के द्वारा भी श्रमिकों के हुनर को एक अलग पहचान मिल रही है। हाल में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार आरपीएल प्रमाणीकरण के बाद लगभग 47 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी आय में वृद्धि हुई है।

कठिन दौर का बजट

जैसी अपेक्षा थी, कोरोना महामारी से संघर्ष के इस दौर में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को खास तवज्जो दी। हेल्थकेयर बजट 94,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.46 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट होना बाकी है कि इस विशाल बजट राशि का इस्तेमाल किस तरह से और किन मदों में किया जाएगा। लेकिन यह बढ़ोतरी असाधारण है और इससे अंदाजा मिलता है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को प्राथमिकता से ले रही है। जिस तरह की असामान्य चुनौतियों के बीच यह बजट आया है, उसमें स्वाभाविक है कि सरकार ने बजट संबंधी पारंपरिक मानदंडों और कसौटियों को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया है। इसी का परिणाम है कि साल 2021 में वित्त घाटा 9.5 फीसदी रहने का अनुमान होने के बावजूद जल्द से जल्द इसको नीचे लाने से ज्यादा जरूरी यह माना गया कि सरकारी खर्च बढ़ाकर विकास की गति को तेज किया जाए। वित्तीय घाटे को कम करने का काम चरणबद्ध ढंग से करते हुए इसे साल 2025-26 तक चार फीसदी से नीचे लाने का लक्ष्य तय किया गया है और फिलहाल पूरा जोर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए असेट क्रिएट करने तथा रोजगार पैदा करने पर रखा गया है।

सरकार ने वित्त घाटे की भरपाई के लिए विशेष कोरोना टैक्स लगाने जैसे कदमों से भी परहेज किया है, जिसका अच्छा असर शेयर बाजारों की पॉजिटिव प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है। बजट भाषण समाप्त होने तक बीएसई सेंसेक्स 3.13 फीसदी और निफ्टी 3 फीसदी चढ़ चुके थे। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने विनिवेश को बढ़ावा देने का इरादा जताया है। शेयरों का ऊपर की तरफ जाने का रुझान इसमें भी मददगार हो सकता है। जहां तक भारतीय बाजार के निचले हिस्से की गतिशीलता का सवाल है तो उस पर उतना जोर अभी भी नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए।

हालांकि बजट में छोटे उद्यमों का दायरा बढ़ाते हुए कहा गया है कि अब 50 लाख के बजाय 2 करोड़ रुपये तक की पेड कैपिटल तथा 20 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली इकाइयों को इसमें शामिल माना जाएगा। चूंकि महामारी और लॉकडाउन का सबसे मारक असर छोटे-मंझोले उद्योगों और दुकानों पर ही पड़ा है और बाजार में दोबारा सकारात्मकता पैदा करने के लिए इनका मजबूत होना जरूरी है, इसलिए इनके पक्ष में और ज्यादा उपाय किए जाने की जरूरत है।

एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि सेक्टर का है जिस पर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शब्द तो बहुत खर्च किए, लेकिन जरूरी कृषि उपजों की खरीदारी के लिए जिम्मेदार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को निवेश के एक बड़े स्रोत लघु बचत योजनाओं से दूर करके उसकी खरीद क्षमता घटा दी। तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक रोक लगा रखी है, लेकिन इस कदम के जरिए सरकार ने नए कृषि कानूनों पर अमल की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। देखें, किसान और कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले

कृषि कानूनों के अमल पर रोक के फैसले में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन नहीं दिखाई पड़ता

जूस का मतलब अभी तक केवल फ्रूट जूस होता था, लेकिन अब उनका स्थान आंवला, गिलोय, एलोवेरा और तुलसी जैसे जूस ने ले लिया है। इसके अलावा काढ़ा भी लोगों की जळ्बान पर ऐसा चढ़ा कि संक्रमण काल में राष्ट्रीय पेय बन गया। इससे लोग न केवल संक्रमण से बचे, बल्कि मौसमी बुखार, जुकाम और सर्दी से भी बचे। इलाज से बेहतर रोकथाम है और यह आयुर्वेद का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह केवल विकल्प नहीं, बल्कि चिकित्सा का मुख्य आधार है जो मानवजाति को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के वायरस से बचा सकता है।

भारत के लोगों में न्यायपालिका के प्रति गहरा भरोसा है। संविधान निर्माताओं ने भी स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय पर हुई बहस में एचवी पातस्कर ने कहा था कि 'ब्रिटेन में न्याय का प्रधान स्रोत सम्राट माना जाता है। हमारे देश में कोई सम्राट नहीं है। एक स्वतंत्र निकाय (न्यायपालिका) जरूरी है। उसे विशेष शक्तियां दी जानी चाहिए।' भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं का स्रोत संविधान है। यहां न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता है। तीनों संस्थाओं की अपनी सीमा और गरिमा है। संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। अनुच्छेद-50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रविधान है। संसद को विधि निर्माण और संविधान संशोधन के अधिकार हैं। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार है। संविधान की कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं है। सबके काम करने की मर्यादा है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सर्वोच्च न्यायपीठ द्वारा तीन कृषि कानूनों को स्थगित करने का मसला विधि विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है। प्रधान न्यायाधीश ने कानून का क्रियान्वयन और कानूनों के स्थगन को अलग-अलग विषय बताया है।

संविधान में संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के पुनर्विलोकन के अधिकार न्यायपालिका को हैं। अनुच्छेद-13 के अनुसार, 'भारत के राज्य क्षेत्र में प्रर्वितत सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह मूल अधिकारों वाले भाग के

अधिकारों से असंगत है।' इसी तरह संविधान के आज्ञामूलक प्रविधानों व संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लघंन करने वाले कानूनों का निरसन भी न्यायपालिका का अधिकार है। उसकी संवैधानिक वैधता की जांच करना न्यायपालिका का अधिकार है। किसी कानून के प्रथमदृष्टया असंवैधानिक पाए जाने पर कानून के प्रवर्तन को रोकने की बात सही हो सकती है, लेकिन कृषि कानून प्रथमदृष्टया भी असंवैधानिक नहीं पाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा है, 'निस्संदेह किसी कानून के असंवैधानिक पाए जाने की स्थिति में न्यायालय उसे शून्य कर सकती है, लेकिन बिना तथ्यों के वह किसी विधि के प्रवर्तन को रोक नहीं सकती।' उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे कोई तथ्य संकलित नहीं किए गए और कानून का प्रवर्तन रोकना दूसरी संस्था के अधिकार में अतिक्रमण है।

कृषि कानूनों पर न्यायालय में विस्तृत विचार नहीं हुआ। कानूनों में अनेक प्रविधान हैं। कायदे से इनकी संवैधानिकता पर विचार करने के लिए धारावार, खंडवार विश्लेषण किया जाना चाहिए था। इन कानूनों के निर्माण की संसद की विधायी क्षमता पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। संसद और विधानमंडल में विधि निर्माण के समय अलग-अलग धाराओं पर और कभी-कभी प्रयुक्त शब्दों पर भी गहन विचार होते हैं। इन कानूनों में मूल अधिकार के उल्लंघन वाले कथित हिस्से पर भी विचार नहीं हुआ और न ही संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करने वाले तथ्य पर। सुप्रीम कोर्ट के प्रति आदर प्रकट करते हुए कहना है कि वह तीनों कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करता तो ज्यादा उचित होता। किसी विधि का निर्माण अथवा उसका निरसन संसद ही कर सकती है अन्य संस्था नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थगन को असाधारण बताया है। कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करने वाले अनेक मामले पहले भी आए हैं। उनमें स्थगन जैसे अंतरिम आदेशों की मांग की गई थी, लेकिन स्थगन नहीं मिला। सबसे चर्चित मसला 'नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019' का था। उस कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे थे। फिर भी कोर्ट ने उस पर स्थगन की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों संबंधी अधिनियम 2003 को प्रवर्तित होने से रोकने के मामले में राहत नहीं दी। 2019 में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले लोग भी निराश हुए। न्यायपीठ ने कहा था कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर हम रोक नहीं लगाएंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में भी कोर्ट ने स्थगनादेश नहीं दिया और न ही आधार मामले में। अन्य मामलों में न्यायालय की कार्यवाही लंबे समय तक चली, पर कृषि कानूनों के मामले में सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कानूनों का निरसन, स्थगन असंवैधानिकता के आधार पर ही होता है, लेकिन यहां न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन नहीं दिखाई पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुधा कहा है कि संविधान में शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण है। राष्ट्र राज्य के सभी अंगों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। इस सीमा का अतिक्रमण संविधान की योजना के विपरीत है।

हमारे संविधान की उद्देशिका में भारत के लोगों का संकल्प उल्लिखित है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से प्राप्त जनादेश के आधार पर ही कार्यपालिका बनती है। विधि निर्माण संसद का काम है। संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सदन है। कृषि कानूनों के मामले में कुछ लोगों के तर्क बड़े दयनीय हैं। वे कहते हैं कि बिना विचार-विमर्श के ही कानून बना लिए गए हैं। उन्हें स्मरण कराया जाए कि कानून निर्माण के पहले सरकार मसौदा तैयार करती है। संसद में अधिनियम रखा जाता है। सदस्य उसका वाचन करते हैं। संशोधन देते हैं। व्यापक बहस के बाद ही कानून बनते हैं। एक अरब 35 लाख की जनसंख्या से किसी भी कानून के निर्माण के पहले परामर्श लेना व्यावहारिक नहीं हो सकता है।

प्रख्यात संसदविद् अर्सकिन ने लिखा है कि 'कोई विधि न्याय विरुद्ध या शासन के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो सकती है, लेकिन संसद के विवेक का नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर वह भूल करती है तो उन भूलों का सुधार भी स्वयं करती है।' संसद की विधि निर्माण शक्ति का निर्वचन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'संसद की प्रभुत्वसंपन्न इच्छा के ऊपर न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं लाद सकती, क्योंकि संसद की इच्छा समस्त जन की इच्छा है। संसद संविधान की सीमा के भीतर है और न्यायपालिका भी। संविधान की सभी संस्थाओं को अपनी-अपनी मर्यादा में उत्कृष्ट काम करना चाहिए।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

ओडिशा में कोरोना संक्रमण का गिरा ग्राफ, प्रदेश में 79 नए संक्रमितों की पहचान

भुवनेश्वर । ओडिशा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। राज्य में सोमवार को 79 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 79 नए मरीजों में से 47 क्वारंटाइन से हैं जबकि 32 स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अनुगुल जिले जिले से 4, बालेश्वर जिले से 7, बरगड़ जिले से 5, बलांगीर जिले से 2, बौद्ध जिले से 1, कटक जिले से 4, गजपति जिले से 2, जाजपुर जिले से 4, झारसुगुड़ा जिले से 3, कालाहांडी जिले से 1, केन्द्रापड़ा जिले से 1, खुर्दा जिले से 14, मयूरभंज जिले से 2, नुआपड़ा जिले से 3, पुरी जिले से 4, रायगड़ा जिले से 1, सम्बलपुर जिले से 4, सोनपुर जिले से 4, सुन्दरगड़ जिले से 10 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा स्टेटपुल में 3 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख 35 हजार 151 तक पहुंच गई है। इसमें से 3 लाख 32 हजार 103 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में 1089 सक्रिय मामले हैं जिनका विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि रविवार को ओडिशा में रविवार को कोरोना संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए थे। नए संक्रमितों में 68 मरीज क्वारंटाइन से थे जबकि 46 स्थानीय लोग संक्रमित थे। नए संक्रमित मरीजों में से सबसे अधिक मरीज सुन्दरगड़ जिले से थे। जिला अनुगुल से 8, बालेश्वर से 7, बरगड़ से 11 बलांगीर से 3, कटक से 7, देवगड़ से एक, गंजाम से 5 जगतसिंह से 2, मयूरभंज से 5, नवरंगपुर से 1, नुआपड़ा से 8, रायगड़ा से 3, जाजपुर से 6 झारसुगुड़ा से 2, खुर्दा से 9, सम्बलपुर से 4 तथा सोनपुर से 1 नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। उसी तरह से स्टेट पुल में 2 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी।

ओडिशा में जारी रहेगी शीत लहर, 10 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे

भुवनेश्वर । ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ा ठंड का प्रकोप अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 10 जगहों पर तापमान 10 डिसे. के नीचे आ गया है। जी.उदयगिरी में रात के समय सर्वनिम्न तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जबकि फुलवाणी में 5 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा में 7.5 डिग्री सेल्सियस, बलांगीर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, केन्दुझर में 8.4 डिग्री सेल्सियस, सोनपुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस, सुन्दगड़ में 9 डिग्री सेल्सियस, बौद्ध में 9 डिग्री सेल्सियस, बारीपाद में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उसी तरह से राजधानी भुवनेश्वर में रात का तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो कटक में 12 डिग्री सेल्सियस पारा रेकर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 4 से 5 दिनों तक समान स्थिति जारी रहने की बात कही है। मिली जानकारी के मुताबिक लगातर हो रहे तापमान गिरावट के कारण झारसुगुड़ा एवं बलांगीर में ठंड के साथ ही शीत लहर जारी है। इसके साथ ही चांदबाली, बालेश्वर, केन्दुझर, फुलवाणी, जी.उदयगिरी, बारीपदा में भी 4 से 5 दिन तक शीत लहर जारी रहने की जानकारी स्थानीय मौसम विभाग से मिली है।

गौरतलब है कि ओडिशा में ठंड गायब हो चुकी थी लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की थी। फरवरी तक ठंड की ऐसी ही लुकाछिपी जारी रहेगी। ठंड के कारण कोहरा भी छाया रहेगा। 1 फरवरी को कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्र, नयागड़, खुर्दा, पुरी, बौद्ध एवं कंधमाल आदि जिला में घना कोहरा छाये रहने की आशंका व्यक्त की गई थी। उसी प्रकार आज 2 फरवरी को तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि दो दिन पश्चात के बाद उत्तर-पश्चिम ओडिशा में पारा फिर गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है ।

महिला विधायक को देख भरी सभा में युवक करने लगा गंदी हरकत, मंच से उतर विधायक ने जड़ा थप्पड़

पटना । बिहार में एक युवक की गंदी हरकत के कारण युवा महिला विधायक ने भरी सभा में अपना आपा खो दिया और मंच से उतरकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह मामला पटना से सटे एक जिले का है। महिला विधायक 30 जनवरी को अपने क्षेत्र के एक गांव में फैंसी क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंची थीं। इस कार्यक्रम में बगल के इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुरुष विधायक भी शामिल थे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस मामले को रफादफा करने के लिए महिला विधायक पर ही दबाव बनाया जा रहा है। महिला विधायक का कहना है कि युवक उन्हें देखककर लगातार अश्लील हरकत कर रहा था। शुरू में विधायक ने उधर से अपनी नजरें हटा लीं और उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन इससे युवक का हौसला और बढ़ गया। इसके बाद तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। विधायक ने जब देखा कि युवक अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला है, तो उन्होंने उसे फटकार भी लगाई। इसके बाद भी युवक नहीं माना तो वे उठीं और उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कार्यक्रम में अप्रिय स्थिति पैदा हो गई। कुछ देर तक वहां रुकने के बाद विधायक कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गईं। बताया जा रहा है कि महिला विधायक को गंदे इशारे करने वाला युवक चार बच्चों का पिता है। विधायक का कहना है कि वह एसपी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं का विरोध करना इसलिए जरूरी है कि यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। अगर ऐसे मामलों में चुप रहा जाए तो गलत लोगों का हौसला और बढ़ेगा और वे दूसरी मां-बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे। विधायक का यह भी कहना है कि इस घटना के बाद कुछ लोगों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए वकालत की। लोगों ने युवक को मंदबुद्धि बताते हुए उसकी हरकत को अनदेखा करने को कहा। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि लोगों के साथ मारपीट करने के लिए उन्हें विधायक नहीं चुना गया है। ऐसे मामले में किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। इसलिए हम विधायक की पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं।

इसी हफ्ते होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, उपेंद्र कुशवाहा बन सकते हैं शिक्षा मंत्री

पटना । नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार का इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार की प्रबल संभावना है। दिल्ली में भाजपा की इस बाबत हुई उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यह माना जा रहा है कि भाजपा ने अपने कोटे से मंत्रियों के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं जदयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा का नाम तेजी से मंत्री पद के लिए सामने आया है। संभावना है कि रालोसपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एक-दो दिनों के भीतर अपनी पार्टी का विलय जदयू में करेंगे। उन्हें जदयू कोटे से शिक्षा मंत्री बनाए जाने की बात तेजी से सियासी गलियारे में चल रही है। इस चर्चा की ठोस वजह भी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा की तीन मुलाकातों में विलय पर सहमति बन गयी है। रालोसपा का जदयू में विलय होते ही उपेंद्र कुशवाहा को जदयू कोटे से राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। इस चर्चा में यह बात भी की जा रही कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि वह केंद्र की राजनीति करते रहें। उनकी जगह उनकी पत्नी को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिले। बाद में उन्हें विधान परिषद भेजा जाए। जदयू की सोच है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर बिहार में लव-कुश समीकरण को मजबूत करने में और मदद मिलेगी। हाल ही में कुशवाहा समाज के नेता को जदयू ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ जोड़कर उन्हें जदयू कोटे से शिक्षा मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके पीछे यह समीकरण है कि पूर्व में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शिक्षा मंत्री थे। वह भी कुशवाहा समाज से आते थे। इस बार वह चुनाव हार गए। इसके बाद कुशवाहा समाज से चुन कर आए मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। बीच में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

यूपी में चौरी चौरा दिवस पर बनेगा अनोखा विश्व रिकॉर्ड, पूरे प्रदेश में एक साथ गूंजेगा वंदेमातरम

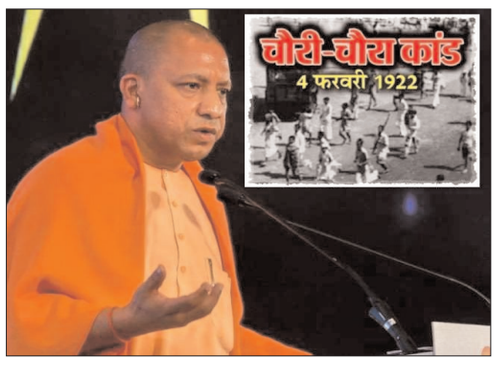

लखनऊ। चौरी चौरा कांड शताब्दी वर्ष महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वंदेमातरम् गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। संस्कृति विभाग तीन से चार फरवरी तक सभी जिलों गायन की व्यवस्था कर रहा है। इस संबंध में प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने शिक्षा विभाग के साथ ही सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चौरी-चौरा और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन करते हुए सैल्यूट मुद्रा में वंदेमातरम् के पहले छंद का गायन कर वीडियो बनाना होगा।

इसके लिए हर जिले में इंटरनेट सुविधायुक्त शैक्षिक संस्थान और अन्य उपयुक्त स्थलों का चयन करना होगा। हर केंद्र के लिए एक नोडल अधिकारी होगा। दो फरवरी को रिहर्सल किया जाएगा। फिर तीन फरवरी को सुबह दस से चार फरवरी दोपहर 12 बजे तक गायन कर वीडियो बनाने होंगे। वीडियो अपलोड करने के लिए तीन फरवरी को सुबह नौ बजे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा वेबसाइट और लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि एक वीडियो में एक ही व्यक्ति सैल्यूट की मुद्रा में नजर आना चाहिए। वीडियो न्यूनतम 20 सेकंड का होना चाहिए, जिसमें उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट रहे।

शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए दीप-प्रज्वलन - आजादी की लड़ाई के सुनहरे अध्याय चौरीचौरा घटना के शताब्दी वर्ष की शुरुआत पर उत्तर प्रदेश में समवेत राष्ट्रगीत वंदेमातरम् गूंजेगा। गोरखपुर जिले स्थित चौरीचौरा स्मृति स्थल से लेकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े स्थान और 1947 से अब तक देश की रक्षा करते हुए शहादत देने वाले अमर शहीदों के स्मृति स्थल, हर कहीं वंदेमातरम् गायन होगा। यही नहीं, चार फरवरी की शाम पूरा प्रदेश सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए दीप-प्रज्वलन भी करेगा।

निर्धारित लय में होगा वंदेमातरम गायन - पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरीचौरा शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों के तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा था कि समवेत वंदेमातरम् गायन के लिए यह जरूरी है कि एक निर्धारित लय में ही गायन हो। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हों अथवा शहीद स्मृति स्थल, सभी स्थानों पर इस संबंध में पूर्वाभ्यास कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभातफेरी के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हो। पुलिस बैंड के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के गीतों भी बजाए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि चार फरवरी, 2021 से चार फरवरी, 2022 तक चलने वाले चौरीचौरा शताब्दी वर्ष समारोह के प्रथम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष उद्बोधन भी होगा। शिक्षण संस्थानों में होंगी विविध प्रतियोगिताएं - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरीचौरा के इतिहास से जुड़े स्तरीय साहित्य युवाओं को उपलब्ध कराने और अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने बेसिक, उच्च, माध्यमिक, कृषि और चिकित्सा शिक्षा विभागों से शताब्दी वर्ष के दौरान वर्षभर होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी ली। कार्ययोजना के मुताबिक शताब्दी समारोह के तहत स्कूलों में निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, काव्य-पाठ, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही, प्रदर्शनियां, पुस्तक मेला तथा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। समारोह के समापन अवसर पर विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

बड़ी खबर, आगरा में दो घंटे पहले ही लीक हो गया था सीटेट का पेपर, छह लोग हिरासत में

आगरा । आगरा में रविवार को 96 केंद्रों पर आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) का पेपर दो घंटे पहले लीक हो गया था। पेपर लीक करने वाले रैकेट ने इसे वाट्सएप ग्रुप में अपने लोगों को शेयर कर दिया था। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने छह संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक करने वाले रैकेट का सरगना प्रयागराज का बताया गया है। पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं।

रविवार को आगरा समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सीटेट आयोजित की गई थी। आगरा में यह परीक्षा 96 केंद्रों पर हुई थी। इसमें 50 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा सुबह और दोपहर दो पालियों में आयोजित की गई थी। आगरा पुलिस को परीक्षा से पहले ही सीटेट का पेपर लीक होने के सुराग मिले थे। यह पेपर रैकेट से जुड़े लोगों ने विभिन्न जिलों में अपने सदस्यों को वाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया था। ठोस सुराग मिलने के बाद पुलिस इस पेपर लीक करने वाले रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी थी। मंगलवार को उसने छह लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली हैं। पेपर लीक करने वाले गिरोह का सरगना प्रयागराज का बताया गया गया है। रैकेट से जुड़े लोग आगरा और इटावा के अलावा अन्य शहरों में भी सक्रिय थे। जिन्होंने पेपर लीक करने के बाद उसे वाट्सएप ग्रुप से अभ्यर्थियों को पहले ही उपलब्ध करा दिया था। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया सीटेट पेपर लीक करने के मामला सामाने आया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत का यूपी के 3.53 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा लाभ

लखनऊ । इस बार के केंद्रीय बजट में भले ही आम लोगों को इनकम टैक्स में कोई छूट न मिली हो, लेकिन बुजुर्गों को केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) नहीं भरने की बड़ी सहूलियत दी है। केंद्र सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 3.53 लाख से अधिक बुजुर्गों को आइटीआर भरने से राहत मिली है। पेंशन के अलावा बैंक जमा के ब्याज से गुजर-बसर करने वाले इन बुजुर्गों को आइटीआर फाइल करने के लिए अब टैक्स कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रदेश में कोषागार के जरिये पेंशन पाने वाले 11,96,237 पेंशनर हैं। इनमें 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स की संख्या 3,53,341 है। इनमें 100 वर्ष से अधिक उम्र के 1431 पेंशनर शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ऐलान किया है कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्स पेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों आइटीआर नहीं भरना होगा। हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट पेश किया। यह बतौर वित्त मंत्री उनका तीसरा बजट था। उन्होंने बजट को छह स्तंभों पर पेश किया। इनमें स्वास्थ्य व कल्याण, भौतिक व वित्तीय पूंजी संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, इनोवेशन और अनुसंधान व विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल हैं। बजट में मध्यम वर्ग के लिए सीधे तौर पर कोई राहत नहीं है। हालांकि आम जनता इस बात पर राहत महसूस कर सकती है कि राजस्व संकट के बावजूद कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। अगले वित्त वर्ष से भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान पर प्राप्त ब्याज को कर के दायरे में लाया गया है, जिसकी चुभन एक बड़ा वेतनभोगी वर्ग महसूस करेगा। पेंशन पर निर्भर 75 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट दी गई है।

भाजपा विधायक अलका राय ने प्रियंका वाड्रा को लिखा पत्र, कहा- पंजाब व राजस्थान सरकार बाहुबली मुख्तार के साथ

लखनऊ । भाजपा विधायक अलका राय ने पंजाब सरकार पर पति के हत्यारे एवं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को फिर एक भावुक पत्र लिखा है। मुहम्मदाबाद से भाजपा विधायक अलका राय ने कांग्रेस नेतृत्व की पंजाब सरकार पर मुख्तार और राजस्थान सरकार पर मुख्तार और उनके इनामिया बेटे अब्बास अंसारी को राज्य अतिथि का दर्जा देते हुए बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सरकार कुख्यात अपराधी के बेटे का करा रही धूमधाम से निकाह...

दरअसल, बीती 30 जनवरी को अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को भेजा। पत्र जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सनसनी फैल गई। पत्र में अलका राय ने कहा कि पंजाब सरकार जहां मुख्तार को बचाने में लगी है। वहीं, राजस्थान सरकार ने उसके इनामिया बेटे को अतिथि का दर्जा दे डाला। सरकारी संरक्षण में अब्बास अंसारी की शादी धूमधाम से कराई गई।

जिसकी फोटो समाचार पत्रों में भी छपी हैं। अलका ने पत्र में भावुक होते हुए कहा कि पति के हत्यारों को इस तरह का संरक्षण आपके नेतृत्व की सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जिससे हम बहुत आहत हैं। मेरे पूरे परिवार का इस बात का कष्ट है। आप महिला होने के नाते कम से कम हमारा दर्द समझेंगी यह हमें उम्मीद थी। क्योंकि आए दिन आप अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के दावे करती रहती हैं। पर आपने हमारे जैसी अनगिनत महिलाओं के पत्र को देखकर न तो आपने जवाब दिया और न ही इंसाफ दिलाना उचित समझा। इससे यह स्पष्ट है कि आप और आपकी सरकार पूरी तरह से मुख्तार और उसके अपराध के पीछे खड़ी है।

27 अक्टूबर को लिखा था पहला पत्र - बता दें, इससे पहले भाजपा विधायक अलका राय ने 27 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को पत्र भेजा था। पत्र में विधायक ने अपने पति कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपित अपराधी मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की गुहार की थी। वह पत्र भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 32 बार भेजा वाहन पर अबतक नहीं भेजा मुख्तार को- अलका राय ने प्रियंका वाड्रा को लिखे पत्र में कहा कि कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की अदालतों में वांछित है। उसे पंजाब से लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32 बार वाहन भेजे। पर आप और आपके नेतृत्व की पंजाब सरकार ने उसे नहीं भेजा। आप और पंजाब सरकार दोनों मुख्तार को बचाने में लगी हैं।

2005 में हुई थी हत्या अलका राय के पति की हत्या, मुख्तार समेत छह पर था आरोप- बता दें, भाजपा विधायक अलका राय के पति कृष्णानन्द राय की 2005 में हत्या कर दी गई थी। वह मौजूदा समय में विधायक थे। इस घटना ने उस वक्त राजनीतिक में बड़ा तूफान ला दिया था।

जब हत्या का आरोप बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, अफजाल अंसारी, राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा। हालांकि, 2019 में दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

तृणमूल के हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़कीं भारती घोष, कहा- बंगाल में है जिहादियों की सरकार

कोलकाता । बंगाल में जैसे- जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं की तीखी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक टीवी डिबेट शो में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने भगवान राम, माता सीता और भगवान परशुराम को लेकर अत्यंत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने भी माता सीता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। तृणमूल नेताओं द्वारा लगातार हिंदू धर्म के अनुयायियों को आहत करनेवाली बयानबाजी पर पूर्व आइपीएस अधिकारी व बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष भारती घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने सत्तारुढ़ दल को इसको लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में जो तृणमूल की सरकार है, वह जिहादियों की सरकार है। हिंदू देवी-देवताओं और उनकी संस्कृति के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। घोष ने कहा- कहने को तो इनके अधिकतर मंत्री हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म को खत्म करने पर तुले हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता हर दिन हिंदुओं व हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तृणमूल सरकार में जितने भी लोग हैं, वह जेहादी हैं। उन्होंने मदन मित्रा द्वारा जय श्रीराम पर बैन लगाने के लिए अदालत जाने के मसले पर कहा कि वह हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट, हम जनता कोर्ट में हैं और जनता जनार्दन ने ही जय श्रीराम कहा है।

एक सभा के दौरान पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष से जब पूछा गया कि इस बार बंगाल चुनाव कितने साफ-सुथरे तरीके से होगा तो उन्होंने कहा, जितनी कोशिश हम चुनाव को साफ-सुथरे तरीके से करवाने का करेंगे, ठीक उतनी ही कोशिश तृणमूल कांग्रेस चुनाव को गंदा करने के लिए करेगी। गंदा करने से उनका तात्पर्य बूथ कैप्चरिंग या वोटर को डराने धमकाने से है। घोष ने कहा कि तृणमूल के लोग जनता के मताधिकार को छीनने की जितना कोशिश करेंगे, उसका 100 गुना अधिक कोशिश हम करेंगे कि राज्य की हर एक जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना मतदान कर सकें।

पूर्व आइपीएस अधिकारी घोष ने दावा किया कि इससे पहले जितने भी चुनाव बंगाल में हुए, उन सब में तृणमूल के लोगों के द्वारा अधिकतर बूथ को कैप्चर कराया जाता था और पोलिंग एजेंट को डराया धमकाया जाता था। बूथ में केवल एक पोलिंग एजेंट दिया जाता था और वह भी तृणमूल के लिए ही काम करता था. ऐसे में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करें भी तो कैसे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले तृणमूल के लोग घर-घर जाकर लोगों को डराया करते थे या वोटर कार्ड छीन लिया करते थे, जिससे कि लोग मतदान न कर सके।

राजनीतिक हिंसा में बंगाल का स्थान सर्वोपरि

भारती घोष ने आगे कहा कि राजनीतिक हिंसा में बंगाल का स्थान सर्वोपरि है। राजनीति के मामले में जितनी हिंसा अन्य राज्यों में की जाती है, उससे कई गुना ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार जनता को धोखा देती है, जैसा कि वह अब स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम पर कर रही हैं।

भारती ने तृणमूल पर आरोप लगाया कि वह चोरी करती है। तृणमूल के नेता कोविड टीका से लेकर के स्लोगन तक चुराते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे- घरे को भी तृणमूल द्वारा चुरा कर हरे कृष्णा, हरे हरे टीएमसी घरे-घरे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं को चोरी करने की आदत ऐसी पड़ चुकी है कि वह वोट भी चुराना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता जनार्दन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- सियासत तू कमाल, बिछाकर कंटीले तार, कहती है आ करें बात

लखनऊ । कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को शायराना अंदाज में ट्वीट कर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सियासत तू है कमाल, उठाके रास्ते में दीवार, बिछाकर कंटीले तार, कहती है आ करें बात। इसके बाद उन्होंने दो हैशटैग किसान और नहीं चाहिए भाजपा लिखा है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के दुख दर्द का अहसास अभी भी नहीं कर रही है। उसे झूठे भुलावों में फंसाए रखना चाहती है। किसानों की राय के बिना थोपे गए कृषि कानूनों पर अभी भी भाजपा सरकार हठधर्मी दिखा रही है, जबकि किसानों के पक्ष में उमड़ा जनभावना का अभूतपूर्व सैलाब दर्शाता हैं उनसे आम जनता कितना दुखी है।

बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में उपद्रव से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम कर रही है। टीकरी और सिंघु समेत दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले दिल्ली के बार्डर पर कहीं चौड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो कहीं सड़क पर नुकीली कीलें लगाई जा रही हैं। जगह-जगह सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि बार्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में दिल्ली में नहीं घुस सकें। सिंघु बार्डर पर सीमेंट कंकरीट की दीवार बना दी गई। वहीं, टीकरी बार्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यहां चार फीट मोटी सीसी की दीवार पहले ही बना दी गई थी। बार्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं।

उपद्रव मामले में छह और एफआइआर, 38 गिरफ्तार - ट्रैक्टर परेड की आड़ में उपद्रव करने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। पुलिस ने छह और एफआइआर दर्ज कर 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 44 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि 122 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उपद्रव में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड से 25-25 हजार व मामूली घायलों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

प्रदेश में तीन दिन बारिश-हिमपात की संभावना, दो दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी

धर्मशाला/शिमला । हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं। मंगलवार को निचले व मध्यम क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। जनजातीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बुधवार और वीरवार को यलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। सोमवार को पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे में चार इंच बर्फ गिरी। राहनीनाला और मढ़ी में भी हल्का हिमपात हुआ। मौसम को देखते हुए लाहुल स्पीति प्रशासन ने पर्यटकों को 11 बजे तक घाटी में नहीं आने की बात कही थी, लेकिन मौसम खुलने पर पर्यटकों को अनुमति दे दी। केलंग में भी दो सेंटीमीटर हिमपात हुआ।

मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि इससे समूचे प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को जनजातीय क्षेत्र केलंग व कल्पा में ही तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया है। प्रदेश में ऊना शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री से अधिक है।

सासे ने जताई हिमस्खलन की आशंका- हिम एवं आवधाव अध्ययन संस्थान सासे मनाली ने मंगलवार को अटल टनल क्षेत्र से सिस्सू लाहुल क्षेत्र में हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को बर्फ वाले क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। एसपी लाहुल स्पीति मानव वर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की है। मंगलवार को अटल टनल सैलानियों के लिए बंद रहेगी। हिमस्खलन को देखते हुए सोलंग तक ही पर्यटक जा पाएंगे।

एक नजर

टीआरएस के विधायक धर्म रेड्डी के बिगड़े बोल, पिछड़ी जाति के अधिकारियों ने खराब किया राज्य को

नई दिल्ली । एक विवादित टिप्पणी में, तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक धर्म रेड्डी ने रविवार को कहा कि राज्य पिछड़ी जातियों के अधिकारियों द्वारा खराब कर दिया गया है। वारंगल में एक बैठक को संबोधित करते हुए, विधायक ने कहा, शीर्ष जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग बहुत अन्याय सह रहे हैं, वे अन्य जातियों की तुलना में गरीब हैं और यह दिखाई दे रहा है। 99 अंक प्राप्त करने के बाद भी वे नौकरी नहीं पा रहे। इस बैठक में भी ऐसे लोग हैं। रेड्डी ने उल्लेख किया कि सभी सरकारी अधिकारियों में पिछड़ी जातियों के अधिकारी शामिल हैं, जो किसी भी काम को नहीं जानते हैं, जिसके कारण राज्य खराब हो गया है, इस मामले के कारण उच्च जातियों में नाराजगी है।

रेड्डी ने आगे कहा- आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र में उदाहरण के लिए, वे हमारे पास आए और कहा कि एक अच्छा अधिकारी (पिछड़ी जाति का अधिकारी) है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने काम में बढ़िया प्रदर्शन किया है। जिसपर उन्होंने हामी भरी और फिर जब उस अधिकारी को यहां लाया गया तो वह एक शब्द भी नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा अधिकारी को क्यों लाए हैं, तो उनका जवाब था कि इनसे हस्ताक्षर देने को कहा जाए, तो हस्ताक्षर करेंगे लेकिन अगर कोई अच्छा अधिकारी आएगा तो हस्ताक्षर करने से इंकार कर देगा। रेड्डी के बयानों का जवाब देते हुए, तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्रवण दासोजु ने सोमवार को टीआरएस विधायक को फटकार लगाई और उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही।

ईडी बड़ी कार्रवाई, जब्त की बिहार-झारखंड के कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव की पत्नी की संपत्ति

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को शीर्ष माओवादी नेता अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव की पत्नी गीता देवी की चल और अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। एक बयान के अनुसार, संलग्न संपत्ति झारखंड के पलामू जिले में स्थित भूमि और गीता देवी के नाम पर बैंक खाते में शेष राशि 16.49 लाख रुपये के रूप में है। अभिजीत यादव एक कुख्यात नक्सली और प्रतिबंधित और आतंकवादी नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) का एक सक्रिय सदस्य और सब-जोनल कमांडर है। पुलिस रिकॉर्ड में वह एक फरार अपराधी है। ईडी ने 3 एफआईआर के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच शुरू की, जिसमें अभिजीत यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे। बयान में कहा गया, ÷उसके खिलाफ लेवी वसूलने, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। अभिजीत यादव बिहार के गया, औरंगाबाद और झारखंड के पलामू जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों से लेवी की धमकी, जबरन और अवैध वसूली कर रहा है।

बयान में कहा गया है, कोर्ट के समक्ष अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव और उसकी पत्नी गीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट से 16.44 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने और संलग्न संपत्तियों को जब्त करने के लिए अभियुक्तों को दंडित करने की अपील की गई थी।

बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, भीड़ जुटाने के लिए एक नेता पांच गांव अभियान

जयपुर । कृषि कानूनों के खिलाफ शाहजहांपुर में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में एक नेता पांच गांव अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष रमन रंघावा ने बताया कि 5 फरवरी को दोनों जिलों से 50-50 गाड़ियों का काफिला शाहजहांपुर जाएगा। किसान नेताओं ने तय किया है कि 5 फरवरी से पहले सभी किसान आंदोलन का प्रत्येक पदाधिकारी पांच-पांच गांवों में जाकर लोगों को शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार करेगा। पिछले एक सप्ताह में प्रमुख किसान नेता गांवों में जाकर आए हैं। अब एक बार फिर जाएंगे। गांवों में जाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाया जा रहा है। करणपुर किसान संघर्ष समिति के संयोजक अमर सिंह विश्नोई ने बताया कि अलग-अलग टीमें बनाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि खेती की रक्षा के लिए वे शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों को बताया जा रहा है कि यदि खेती पर संकट आएगा तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होनी शुरू हो जाएगी। इस कारण आंदोलन को सफल बनाना जरूरी है। आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने से सभी का फायदा होगा। उधर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले तीन दिन से आसपास के ग्रामीणों ने शाहजहांपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने की कोशिश की। लेकिन किसानों और ग्रामीणों के बीच बातचीत के बाद मामला वहीं खत्म हो गया। किसान वहां से हटे नहीं। सोमवार शाम से किसानों की संख्या में फिर बढ़ोतरी होने लगी है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनूं गांवों से किसान पहुंचे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी विधायकों को बारी-बारी से शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचने के लिए कहा है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील के नेतृत्व में जाट समाज के लोग भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।

बड़ी लापरवाही, बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह पिला दिया हैंड सैनिटाइजर

मुंबई । महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कापसिकोपरी गांव से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यवतमाल जिले के कापसिकोपरी गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दी गई। सभी बच्चों की उम्र पांच साल से कम है। मामला तब सामने आया जब ड्रॉप लेने के बाद बच?चों की हालत बिगड़ने लगी उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम इन बच?चों की निगरानी कर रही है। इस बड़ी लापरवाही के मामले में भानबोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर, आंगनबाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिला परिषद के सीइओ श्रीकृष्ण पंचाल के अनुसार बच्चों की हालत अभी स्थिर है।

ये घटना रविवार को कापसिकोपरी गांव के भानबोरा पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में हुई थी। यहां 1-5 साल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चल रहा था। यवतमाल जिला परिषद के सीईओ श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि 5 साल से कम उम्र के 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स के स्थान पर दो बूंदें सैनिटाइजर दे दी गई। इसके बाद, बच्चे उल्टी और बेचैनी की शिकायत करने लगे। पांचाल ने कहा कि जिन बच्चों को यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं, उनकी हालत स्थिर बतायी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस समय ये घटना हई उस समय तीन स्वास्थ्य कर्मचारी, एक डॉक्टर, आंगनवाड़ी सेविका और एक आशा स्वयंसेवक पीएचसी में मौजूद थे। इस मामले की जांच चल रही है तीनों स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए जाएंगे। इस बीच, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि घटना तब सामने आई जब गांव के सरपंच ने बूंदों की जांच की और पाया कि ये हैंड सैनिटाइजर है न कि पोलियो खुराक। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके के लोगों के बीच भय का माहौल है जिसे लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।यवतमाल कलेक्टर एम डी सिंह ने अस्पताल का दौरा किया और बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

गुजरात कांग्रेस ने की पांच महानगर पालिका के 130 उम्मीदवारों की घोषणा

अहमदाबाद । गुजरात कांग्रेस ने पांच महानगर पालिका के 130 उम्मीदवारों की घोषणा कर इस बार प्रत्याशी घोषित करने में पहल दिखाई है। अहमदाबाद महानगरपालिका उम्मीदवारों की भी घोषणा होनी थी लेकिन नेताओं में सहमति नहीं बन पाने से यह सूची अटक गई। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर पता भावनगर महानगर पालिका के 61 वार्ड में सवा सौ से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीते तीन-चार दिनों से कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक मैं 6 महानगर पालिका में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई।

राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट

जयपुर । राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हुई है। कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का प्रयास है कि 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार करने के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का काम शुरू कर दिया जाए।

पार्टी आलाकमान चाहता है कि बजट सत्र से पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के दो से तीन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हालांकि सीएम गहलोत विधानसभा सत्र और चार सीटों होने होने वाले उप चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार करने के पक्ष में नही है। लेकिन आलाकमान लगातार दबाव बना रहा है। इसी लिहाज से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अजय माकन बुधवार को जयपुर में गहलोत, पायलट व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठक करेंगे। माकन का प्रयास रहेगा कि सभी नेता मंत्रिमंडल विस्तार व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सहमत हो जाएं। पायलट तो पिछले तीन माह से लगातार पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं कि उनके समर्थक विधायकों व नेताओं को मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान दिया जाए।

पायलट की अपने समर्थक विधायकों के साथ हुई बगावत और फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दखल के बाद वापस लौटते समय यह तय हुआ था कि उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल एवं राजनीतिक नियुक्तियों में उचित महत्व दिया जाएगा। ये दोनों काम जनवरी माह में पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन गहलोत पायलट समर्थकों को सरकार में पद देने के पक्ष में नहीं है, ऐसे में वे लगातार मंत्रिमंडल विस्तार टाल रहे हैं।

गहलोत आलाकमान के समक्ष तर्क दे रहे हैं कि यदि उप चुनाव और विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया तो विधायकों की नाराजगी बढ़ सकती है। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल अथवा राजनीतिक नियुक्तियों में जगह नहीं मिलेगी वे नाराज हो सकते हैं। हालांकि आलाकमान शीघ्र यह काम पूरा करना चाहता है। इसी कारण से अजय माकन बुधवार को गहलोत, पायलट व डोटासरा के साथ बैठक करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि बजट सत्र से पहले सरकार में नियुक्तियों का काम पूरा हो जाए।

बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति कर रहा है केंद्र : शिवसेना

मुंबई । शिवसेना ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन कुछ राज्यों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है जहां आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। उसने पूछा कि क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है।

शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि उन राज्यों को अधिक धन आवंटित करना घूस देने के समान है जहां आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसने केंद्र पर बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति करने का नया चलन शुरू करने का आरोप लगाया।

शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कोष में सर्वाधिक राजस्व का योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र की केन्द्र ने उपेक्षा की। सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया।

संपादकीय में कहा गया कि

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि (केंद्र) सरकार ने बजट के जरिए वोटों की गंदी राजनीति का खेल खेलने का नया चलन शुरू किया है। संपादकीय के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए वित्तमंत्री ने उन राज्यों को बड़े पैकेज और परियोजनाएं का आवंटन किया।

उसमें कहा गया है कि नासिक और नागपुर मेट्रो परियोजनाओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर बजट में मुंबई और महाराष्ट्र के हाथ कुछ नहीं आया। केंद्र ने नासिक मेट्रो के लिए बजट में 2,092 करोड़ रुपये का और नागपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 5,976 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शिवसेना ने सवाल किया कि यह भेदभाव क्यों?

किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, भाजपा नहीं हुई शामिल

नई दिल्ली । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पंजाब भवन पहुंचे। जानकारी है कि इस सर्वदलीय बैठक में भाजपा(पंजाब) हिस्सा नहीं लेगी।

बैठक के संबंध में पंजाब सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि बैठक शाम चार बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसका एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। हाल ही में अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हमारे किसान दिल्ली की सरहदों पर दो महीने से भी अधिक समय से अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। पुलिस उनकी पिटाई कर रही है और गुंडों द्वारा किसानों पर हमले किए जा रहे हैं। उनको प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित रखकर परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को किसानों की हिमायत और पंजाब के हितों को मुख्य रखते हुए एकजुट होकर इस बैठक में शिरकत करने का न्योता देते हुए कहा कि कृषि कानूनों से पैदा हुआ संकट समूचे राज्य और इसके लोगों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि समूह पंजाबियों के साझे यत्नों और राज्य के सभी राजनीतिक दलों के एक साथ इस समस्या को प्रभावी ढंग से निपटने के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय बजट 2021-22 के खिलाफ, विशाखापत्तनम में गांधी प्रतिमा के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अपना सिर मुड़वाते हुए।

गिरफ्तार ड्रग सप्लायर चीकू पठान की तबियत बिगड़ी,अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली । नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे परवेज खान उर्फ चिंकू पठान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। पठान के बीमार पड़ने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग एंगल सामने आने से बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफी सक्रिय है और लगातार छापेमारी कर रहा है। हाल ही में मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने चिंकू पठान के ड्रग कार्टेल के संबंध में जुहू इलाके में छापेमारी की थी। गौरतलब है कि पठान एक कुख्यात ड्रग सप्लायर है और उसके खिलाफ कई मामले पहले से लंबित हैं। कुछ ड्रग पैडलर से भी उसके संबंध हैं, जिन्हें हाल के महीनों में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने खास सूचना के आधार पर खान को दबोच लिया। चिंकू पठान उस करीम लाला का रिश्तेदार है, जो 1960 के दशक से 80 के शुरुआती दशक तक मुंबई में अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा था।

यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध जोधपुर नगर निगम का विशेष अभियान

जोधपुर । राज्य सरकार की ओर से बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर छूट दिए जाने के बावजूद भी बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध नगर निगम (दक्षिण) की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है, इसके लिए तीन दलों का गठन किया गया है।

नगर निगम आयुक्त (दक्षिण) डॉ.अमित यादव ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने नगरीय विकास कर व गृह कर जमा कराने को लेकर विशेष छूट दी गई थी, यह छूट अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी, लेकिन आमजन की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इस छूट को अब 31 मार्च तक बढ़ाया था। आयुक्त (दक्षिण) डॉ. अमित यादव ने बताया कि नगरीय विकास कर के जमा कराने पर भी विशेष छूट दी गई है। 2019- 2020 तक के बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व शास्ति पर शत प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है वहीं 2011-12 के पूर्व के बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर नगरीय विकास कर की राशि में 50त्न छूट दी जाएगी साथ ही ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत

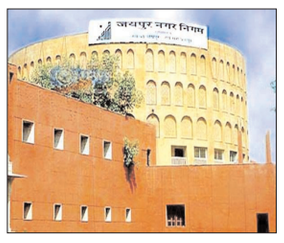

छूट दी जा रही है।

आयुक्त यादव ने बताया कि निगम की ओर से अधिकांश बकायेदारों को बकाया जमा करने का अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। अब बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध 1 फरवरी से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के लिए तीन अलग-अलग दल गठित किए गए हैं, जो अपने-अपने आवंटित वार्ड में जाकर बकायेदारों से बकाया वसूल करेंगे, साथ ही बकाया जमा नहीं करवाने वालों के पर उनके विरूद्ध भवन सीज करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

शास्त्री नगर में करीब 8 करोड रुपए का यूडी टैक्स है बकाया

नगर निगम आयुक्त (दक्षिण) डॉ.अमित यादव ने बताया कि निगम की ओर से क्षेत्र वार बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शहर के शास्त्री नगर में करीब 763 नोटिस जारी किए गए हैं जिनका लगभग 8 करोड रुपए से अधिक का यूडी टैक्स बकाया है। इनमें से 583 नोटिस आवासीय मकानों के हैं वही 151 नोटिस व्यवसायिक भवनों के हैं

ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं यूडी टैक्स- आयुक्त (दक्षिण) डॉ.अमित यादव ने बताया कि कोरोना के संक्रमण काल में कई लोग अनावश्यक रूप से कहीं आने जाने से कतरा रहे हैं, ऐसे में आम जन की मांग को देखते हुए नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया शुरू की है। नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट www.jodhpurmc.org के होम पेज पर जाकर सिटीजन सर्विस का विकल्प चुनेंगे। सिटीजन सर्विस में यूडी टैक्स और हाउस टैक्स के लिंक पर क्लिक करने से शहरवासी अपने बकाया कर के बारे में जानकारी ले सकेंगे, साथ ही ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प को चुन कर अपना बकाया कर ऑनलाइन ही जमा करा सकेंगे। निगम आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि शहरवासी अधिक से अधिक इस छूट का लाभ उठाए साथ ही शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं।

गुजरात भाजपा अध्यक्ष की नई गाइडलाइन, 60 साल से ज्यादा उम्रवालों को नहीं मिलेगा टिकट, लिए कई और फैसले

सूरत । गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की संकलन समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के नेतृत्व में आयोजित की गयी थी। जिसमें पार्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। साथ ही कई निर्णय ऐसे रहे है, जिन्हें सुनकर हर कार्यकर्ता हैरान सा रह गया।

इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि अब 60 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो कॉर्पोरेटर और पदाधिकारी तीन टर्म में पद रहे हैं, उनके सगे-संबंधियों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा संसदीय बोर्ड में लिए गए निर्णयों की घोषणा करते ही कहीं खुशी और कहीं गम वाला माहौल रहा। साथ ही जिन युवा कार्यकर्ताओं और कभी भी पार्टी द्वारा लाभ न पाने वाले दावेदारों में खुशी छा गई। बताया जा रहा है कि इस निर्णय से सूरत में 40 से 50 फीसदी सिटिंग कार्पोरेटरों का पत्ता कट जाएगा। कुछ कार्यकर्त्ता इस दांव को धोबी पछाड़ करार दे रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में जारी गुटबाजी को अपने एक ही दांव से चित्त कर दिया है। गौरतलब है कि, पहले भी सीआर पाटिल ने पेज कमेटी के एक कार्यक्रम में कहा था कि 55 साल से अधिक उम्र के कार्यकर्ता टिकट न मांगें। जिसके चलते पार्टी में तनातनी का माहौल बन गया था।

इसके बाद संकलन बैठक में विधायकों ने विरोध करते हुए कहा था कि 55 साल से अधिक उम्र लोगों को कोई पद नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हालांकि, बाद में विधायको को अनेक समितिओं में पदाधिकारी बनाए जाने की मांग में राजी हो गए थे।

राजस्थान में बीकानेर के भीखाराम साइकिल से दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश

उदयपुर । 'पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाओ, और प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाओ' का संदेश प्रतिध्वनित करने के लिए साईकिल पर राजस्थान भ्रमण पर निकले बीकानेर के नोखा निवासी भीखाराम चाहर सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचकर उन्होंने जिला कलक्टर चेतन देवड़ा से मुलाकात की और अपने जनजागृति अभियान के बारे में जानकारी दी। कलक्टर ने भीखाराम की हौंसला अफजाई करते हुए उनके इस अभियान को सराहा और उन्हें इस नेक कार्य के लिए बधाई दी।

पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाओ, और प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाओ' का संदेश प्रतिध्वनित करने के लिए साईकिल पर राजस्थान भ्रमण पर निकले बीकानेर के नोखा निवासी भीखाराम चाहर सोमवार को उदयपुर पहुंचे। चाहर ने बताया कि 6 दिसंबर को बीकानेर कलक्टर ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली उनकी साइकिल यात्रा को रवाना किया। पूरे राजस्थान की चार हजार किलोमीटर की इस यात्रा को तीन माह में पूरा करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे चाहर अब तक 26 जिलों में घूमकर 3200 किमी का सफर तय कर चुके है। इस दौरान वे आमजन को पर्यावरण संरक्षण के साथ दैनिक जीवन में साइकिल का उपयोग कर स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे है।

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता.उदयपुर सिटी कोलकाता साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 4 फरवरी 21 से शुरू की जा रही है। गाडी संख्या 02315, कोलकाता.उदयपुर सिटी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा कोलकाता से 04 फरवरी 21 से अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक गुरुवार को 13 बजकर 10 बजे रवाना होकर तीसरे दिन 00.25 बजे उदयपुर सिटी पहुचेगी। इसी प्रकार 02316, उदयपुर सिटी.कोलकाता सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा उदयपुर सिटी से 08 फरवरी 21 से अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक सोमवार को 00.45 बजे रवाना होकर दूसरे दिन 14 बजरक 45 बजे कोलकाता पहुचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में वर्धमान, आसनसोल, मधुपुर जं. जसीडीह जं. झाझा, पटना, पं. दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर सेट्रल, टूण्डला, आगरा फोर्ट, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाडा, चंदेरिया, मावली जं व राणाप्रतापनगर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

गाजीपुर बॉर्डर पहुंच शिवसेना नेता राउत ने की टिकैत से मुलाकात, कहा- किसानों से उचित तरीके से बात करे सरकार

मुंबई । शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत गाजीपुर बार्डर पहुंच केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हमने टिकैत साहब से बात की, अपना संदेश दिया और एकजुटता व्यक्त की। सरकार को किसानों से उचित तरीके से बात करनी चाहिए। अहंकार देश को चलाने में मदद नहीं करेगा। संजय राउत सिंघु बार्डर भी जाएंगे। बता दें कि किसानों की रैली में अब सियासत का तड़का जमकर लग रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं।

शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंच रहे हैं। राउत ने ट्वीट में लिखा था कि, ÷महाविकास अघाड़ी सरकार ने किसानों के हित में कई निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ठाकरे संकट के समय किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की बढ़ रही परेशानी और उनके आंसू परेशान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से मिली सूचना के बाद मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से 1ः00

बजे मुलाकात करूंगा। जय जवान-जय किसान।÷।

सोमवार को सिंघु बॉर्डर के नजदीक किसानों ने बैठक की, जिसमें उन?होंने 5 से 6 मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। 6 फरवरी को दिन के 12ः00 बजे से 3ः00 बजे तक पूरे देशभर में संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की जा रही है।

जानें क्या है विरोध की वजह

सरकार ने जो विधेयक लागू किए हैं उनसे किसान और व्यापारियों को एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 के अनुसार में किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। इस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मंडी शुल्क व अन्य उपकर लगाये गए हैं। जिसकी वजह से आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर सता रहा है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो मंडी में कोई नहीं आएगा। किसानों को डर है कि नए कानूनों के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। बता दें कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं की है। मंडी के बाहर जो खरीद की जाएगी, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम भाव पर नहीं होगी।

मौनी रॉय ने स्विमिंग पूल में मचाया तहलका, बोल्ड फोटोशूट ने छुड़ाए सर्दी में पसीने

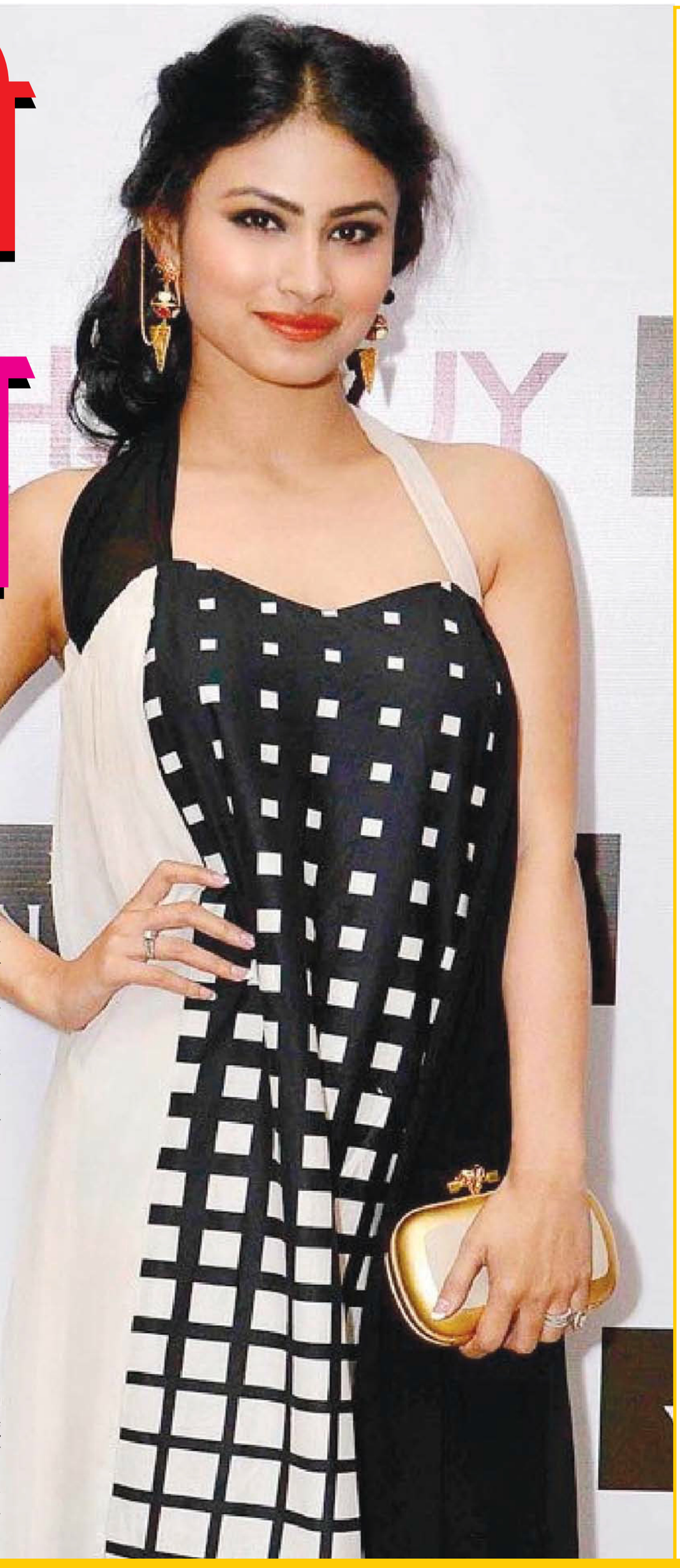

टीवी की नागिन रह चुकीं मौनी रॉय (Mouni Roy) अब बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जादू दिखा रही हैं. सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फोटो और वीडियो से सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में उन्होंने फिर से एक फोटोशूट कराया है, जिसकी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

मौनी रॉय (Mouni Roy) ने बिकिनी पहनकर स्विमिंग पूल में बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया है. तस्वीरों में वह काफी ग्लैमरस लग रही हैं.

तस्वीरों में मौनी तो पूल में आराम फरमाती नजर आ रही हैं लेकिन उन्हें देख लोगों की नींदे उड़ गई हैं. एक्ट्रेस तस्वीरों में किसी जल परी से कम नहीं लग रही हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके फैंस के सर्दी में पसीने छूट रहे हैं.

मौनी पहले भी अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस के होश उड़ाती आई हैं पर एक्ट्रेस

के नए फोटोशूट ने फैंस का दिल जीत लिया है.तस्वीरों में मौनी रॉय की आदाएं लोगों को काफी पसंद आ रही हैं. तस्वीरों पर फैंस ही नहीं मौनी के दोस्त भी लाइक करने के साथ-साथ इस पर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

सुपरहिट टीवी सीरियल नागिन से घर-घर में मशहूर होने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में एंट्री की थी. मौनी रॉय जल्द ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली हैं.

सुशांत सिंह Rajput के भाई को बदमाशों ने मारी गोली, सदमे में है परिवार

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके परिवार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के कजिन (ममेरे भाई) को बदमाशों ने गोली मार दी. वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं.

सुशांत के रिश्तेदार के साथ हादसा

ये घटना बिहार के सहरसा में उस वक्त हुई जब सुशांत के कजिन अपने दोस्त और यामहा शोरुम के मालिक राजकुमार सिंह (Rajkumar Singh) और उनके एक सहयोगी के साथ जा रहे थे. इसी वक्त वहां मोटरसाइकिल पर सवाल कुछ बदमाश आए और तीनों पर गोलियां चला दीं. इस घटना के बाद तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में खौफ का माहौल है.

तीन बदमाशों ने किया हमला

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राजकुमार सिंह (Rajkumar Singh) हर रोज इसी रास्ते से मधेपुरा में अपने शोरूम जाया करते थे. घटना के दिन भी ये तीनों लोग मधेपुरा जा रहे थे. इसी समय बैजनाथपुर चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग आए और सुशांत के कजिन, राजकुमार और उनके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. घटना के पीछे क्या वजह रही फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है.

सुशांत मामले की जांच जारी

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता पटना में रहते हैं. उनका पूरा परिवार और रिश्तेदार मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं. अभी तक दिवंगत अभिनेता का परिवार एक्टर बेटे की मौत की गुत्थी को सुलझाने की ही लड़ाई लड़ रहा है. इस बीच उनके परिवार के करीबी रिश्तेदार पर हमला और भी चौंकाने वाला है. सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही हैं. हालांकि लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सीबीआई ने इस मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है.

अनन्या पांडे का एक और सरप्राइज, VIDEO देख हो जाएंगे मदहोश

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. कई बार इसके पीछे की वजह उनकी सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, जिनमें वे अपनी हॉट पिक्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में वे छुट्टियां मनाने मालदीव्स (Maldives) गई थीं और उन्होंने वहां के खूबसूरत बीच पर क्लिक की गईं अपनी कई फोटो भी शेयर की थीं. एक बार फिर उन्होंने अपनी इन वेकेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जो सुर्खियों में है.

इनफिनिटी पूल में नहा रहीं है अनन्या इस वीडियो में अनन्या पांडे (Ananya Panday) इनफिनिटी पूल में नहाती नजर आ रही हैं. मालदीव्स का उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अनन्या ने कैप्शन में लिखा है- प्रॉमिस, यह मेरी आखिरी मालदीव्स पोस्ट है. उनका यह वीडियो इतना पसंद किया जा रहा है कि इसे पोस्ट करने के बाद 14 घंटे में ही 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. खैर, अनन्या की हालिया पोस्ट से पता चलता रहा है कि उन्हें अपनी यह ट्रिप कितनी ज्यादा पसंद आई है और वह इसे कितना मिस कर रही हैं.

लाइगर में नजर आएंगी अनन्या अनन्या पांडे (Ananya Panday) अब विजय देवरकोंडा के साथ लाइगर में नजर आएंगी. इससे पहले वह ईशान खट्टर के साथ खाली-पीली में नजर आई थीं. बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बाद साल के आखिर में कई बॉलीवुड सेलेब्स छुट्टियां मनाने बाहर गए थे. इसमें से टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मालदीव्स ही गए थे. लिहाजा इन सभी की फोटो सोशल मीडिया पर भी खासी वायरल हुईं थीं.

जरीन खान ने कैटरीना कैफ को बताया अपना करियर चोपट होने की वजह, दिया ऐसा बयान!

बॉलीवुड में जिस दौर में कैटरीना कैफ (Kaitrina Kaif) का एकक्षत्र राज था उस समय एक्ट्रेस जरीन खान (Zareen Khan) ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म वीर से बॉलीवुड में कदम रखा था. तब से लगातार जरीन खान (Zareen Khan) की तुलना कैटरीना से की जाती रही है. वहीं अब जरीन खान ने कैटरीना को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर सलमान खान (Salman Khan) दंग रह जाएंगे. जी हां! जरीन ने अपने करियर को खराब करने का ठीकरा कैटरीना के सिर पर मढ़ दिया है.

निराशाजनक था कंपेरिजन करना

हाल ही में एक मीडिया हाउस से हुई बातचीत में जरीन खान (Zareen Khan) ने अपने करियर को लेकर एक बड़ी बात कही है. इस इंटरव्यू में जरीन ने कहा, जब मैंने बॉलीवुड डेब्यू किया तब मुझे कैटरीना कैफ से कम्पेयर किया गया. यह बहुत ही निराशाजनक होता था.

पहले भी हुए हैं ऐसे कंपेरिजन इसके आगे बात करते हुए जरीन खान (Zareen Khan) ने बताया, इस तरह की बातों से मैंने हार नहीं मानी. इससे पहले भी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था. प्रीति जिंटा को अमृता सिंह से और अमीषा पटेल को नीलम से कम्पेयर किया गया था.

फिल्म की नाकामयाबी की जिम्मेदारी जरीन पर!

इसके आगे जरीन कहती हैं, %शुरू से मेरे लिए करियर की राह में काफी मुश्किलें थीं. जब %वीर% नहीं चली तो लोगों ने इसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराया. उस वक्त मैं नई थी और परफेक्ट नहीं थी. शायद कोई मुझे नहीं समझ पाया. मैं लोगों के लिए सॉफ्ट टार्गेट बन गई थी.

काम मिलना हुआ मुश्किल

जरीन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पहली फिल्म के बाद उन्हें काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था. जरीन ने यह भी कहा कि कैटरीना कैफ की लुकअलाइक होने के चलते उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचा है. जरीन के अनुसार, कोई भी फिल्ममेकर किसी के लुकअलाइक या डुप्लीकेट के साथ काम करना पसंद नहीं करता है.

संक्षिप्त समाचार

निर्यात में वृद्धि सकारात्मक संकेत

नई दिल्ली। विदेश व्यापार कारोबारियों के संगठन भारतीय निर्यातक महासंघ फियो ने जनवरी 2021 में निर्यात में वृद्धि होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने मंगलवार को यहां कहा कि इस वर्ष जनवरी में विदेश व्यापार के आंकड़े सकारात्मक रहे हैं। लगभग सभी प्रमुख जिंसों में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है। इनसें साफ संकेत मिलता है कि आने समय में निर्यात में बढ़ोतरी होती रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की प्रभावी वैक्सीन से न केवल समाजिक जीवन बल्कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट रही है। श्री सराफ ने कहा कि आंकड़ों ने संकेत दिया है कि श्रम आधारित उद्योग जैसे रत्न एवं आभूषण उद्योग के बुरे दिन गुजर चुके हैं और इनमें कामकाज तेजी से सामान्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को रोडटेप योजना को जल्द से जल्द अधिसूचित कर देना चाहिए जिससे कारोबार में अनिश्चितता समाप्त हो सके और विदेशों में नये अनुबंध किये जा सके। इसके अलावा सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं को भी स्पष्ट कर देना चाहिए।

यूएसआईएसपीएफ ने की बजट की तारीफ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2021-22 की तारीफ करते हुए अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं साझेदारी मंच यूएसआईएसपीएफ ने इसे साहसिक और दूरदर्शी बताया जो अर्थव्यवस्था को एक वृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाएगा। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा, हम भारत के बजट की सराहना करते हैं। यह अर्थव्यवस्था को वृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला और साहसिक कदम है। बजट भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक है। उन्होंने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रक्षा में सरकारी खर्च बढ़ा है। उन्होंने आगे कहा, हम मानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के साथ ही बीमा जैसे क्षेत्रों को खोलने और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने से अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यूएसआईएसपीएफ को विश्वास है कि वैश्विक निवेशक समुदाय अगले 12-24 महीनों में भारत की वृद्धि में सहभागी बनेगा।

होटल कमरों पर जीएसटी घटाने को लेकर विचार नहीं

नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय ने होटलों के सभी कमरों पर माल एवं सेवा कर जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत करने के लिए जीएसटी परिषद से अनुरोध करने की कोई योजना नहीं बनाई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पटेल ने कहा कि मंत्रालय इस बात से अवगत है कि होटलों समेत पर्यटन की अनेक सेवाओं पर लगने वाले कर से दूसरे देशों के मुकाबले देश के पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा, इस समय पर्यटन मंत्रालय की होटलों के सभी तरह के कमरों पर जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत करने का अनुरोध करने की कोई योजना नहीं है। जीएसटी परिषद कारोबार के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करने के बाद तथा अर्थव्यवस्था के चतुर्दिक विकास के लिए जरूरी राजस्व अर्जित करने के लिए करों की दर पर फैसला करती है।

बजाज की बिक्री में आठ फीसदी इजाफा

नई दिल्ली। बाजाज ऑटो लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि उसकी कुल बिक्री जनवरी 2021 में आठ प्रतिशत बढ़कर 425199 इकाई हो गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले साल इसी महीने में 394473 इकाइयां बेची थीं। बजाज ऑटो ने बताया कि इस दौरान उसके दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 384936 इकाई रही, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले साल जनवरी के मुकाबले मामूली कमी आई, जिसकी भरपाई बजाज ऑटो ने निर्यात में बढ़ोतरी से कीए जिसमें रिकॉर्ड 30 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। बजाज ऑटो ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों की कुल बिक्री जनवरी में 35 प्रतिशत घटकर 40263 इकाई रही।

बजट से लगे शेयर बाजार को पंख

दूसरे दिन भी लंबी उड़ान, सेंसेक्स 1197 अंक चढ़कर बंद

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से शेयर बाजार को पंख लग लग गए हैं। सोमवार के बाद मंगलवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी ने लंगी उड़ान भरी है। सोमवार को इसमें ऐतिहासिक तेजी आई थी जो मंगलवार को भी बरकरार रही। बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 1197 अंक यानी 2.46 फीसदी की तेजी के साथ 49797.72 अंक पर पहुंच गया। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 367 अंक यानी 2.57 फीसदी की तेजी के साथ 14648 अंक पर आ गया। दो दिन में सेंसेक्स 3500 अंक चढ़ गया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 50154.48 अंक से उच्चतम और 49193.26 अंक के न्यूनतम स्तर को छुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एलएंडटी के शेयरों में पांच से सात फीसदी की तेजी आई। निफ्टी के शेयरों में श्री सीमेंट, टाटा मोटर्स और हिंडाल्को के शेयरों में 6 से 15 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। 2 फरवरी को कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने एक बार फिर 50154.48 को छुआ। इंडेक्स ने 21 जनवरी 2021 को पहली बार 50 हजार का आंकड़ा पार किया था। बाजार की तेजी में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर 3114 में कारोबार हुआ। 1761 शेयर बढ़त और 1179 गिरावट के साथ बंद हुए हैं।

बाजार में बढ़त के कारण

ज्यादातर बाजार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ओवरऑल बजट शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव है। क्योंकि, इसमें नया टैक्स नहीं लगाया है। साथ ही कोरोना सेस की बात भी नहीं हुई, जिससे बाजार लगातार 6 कारोबारी दिन से फिसल रहा था। घरेलू बाजार को वैश्विक बाजारों में बढ़त का भी सपोर्ट मिला। इसमें चीन, जापान, कोरिया सहित यूरोपियन और अमेरिकी शेयर बाजार शामिल है। इसके अलावा अमेरिका में नए कोरोना राहत पैकेज के पॉजिटिव अपडेट का भी असर पड़ा है। मजबूत घरेलू संकेत बाजार के दिग्गज शेयर अच्छी बढ़त के साथ कारोबार किया।

वैश्विक बाजार में मजबूत तेजी

ग्लोबल मार्केट भी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कोरिया का कोस्पी 1.32 फीसदी ऊपर बंद हुआ है। हॉन्गकॉन्ग का हेंगसेंग इंडेक्स और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज इंडेक्स भी एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा जापान का निक्केई इंडेक्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1-1 फीसदी की बढ़त रही। इससे पहले अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों में भी तेजी रही थी। नैस्डैक इंडेक्स 2.55 फीसदी, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.61 फीसदी ऊपर बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट में फ्रांस का सीएसी इंडेक्स और जर्मनी का डीएएक्स इंडेक्स में भी 1-1 फीसदी बढ़त रही थी।

कंपनियों की पूंजी चार लाख करोड़ रुपए बढ़ी

सूचिबद्ध कंपनियों की पूंजी करीब चार लाख करोड़ रुपए बढ़कर 196.68 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो सोमवार को 192.62 लाख करोड़ रुपए थी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स चार फीसदी और बैंक इंडेक्स 3.56 फीसदी ऊपर बंद हुए हैं। दो दिन से बाजार की बढ़त को बैंकिंग शेयरों का सपोर्ट मिल रहा है। इस दौरान निफ्टी बैंक इंडेक्स 12 फीसदी से ऊपर चढ़ चुका है। इसमें प्रमुख रूप से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक के शेयर शामिल हैं। सोमवार को बजट में सरकार ने बुरे फंसे कर्ज एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक की घोषणा की है। इसके तहत सभी एनपीए एक जगह लाए जाएंगे। क्योंकि इससे एनपीए रिजॉल्यूशन में आसानी होगी। बजट में आईडीबीआई और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अलावा दो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का प्रस्ताव पेश किया गया। सरकारी बैंकों के कैपिटलाइजेशन में मदद के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 200 अरब रुपए का रीकैपिटलाइजेशन का ऐलान किया गया। इससे सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी है।

ऑटो शेयरों में शानदार तेजी

सरकार ने बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इसके चलते ऑटो शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स का शेयर सबसे ज्यादा 17 फीसदी ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा अशोक लेलैंड में 9 फीसदी और टीवीएस मोटर के शेयरों में भी 8 फीसदी की बढ़त रही।

राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक

फिच रेटिंग का कहना

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी फिच ने आम बजट पर अपनी टिप्पणी में कहा कि निकट अवधि में भारत का राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक है और मध्यम अवधि में समेकन की गति उम्मीद से धीमी है। भारत, जिसे फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से अक्सर शिकायत रहती है कि उनकी रेटिंग अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ने आम बजट 2021-22 में कहा कि इस समय राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से अधिक है, जबकि उसका लक्ष्य इसे 3.5 प्रतिशत पर रखने का था। अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.8 प्रतिशत है। फिच रेटिंग्स की एशिया-प्रशांत सावरेन दल के निदेशक जेरेमी जुक ने कहा, भारत में केंद्र सरकार द्वारा एक फरवरी को पेश किए गए बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अधिक है, मध्यम अवधि में समेकन उम्मीद से अधिक धीमा है।

जूक ने आगे कहा, हमने वृद्धि संभावनाओं और भारी सार्वजनिक ऋण की चुनौतियों तथा महामारी के प्रकोप के मद्देनजर जून 2020 में नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत की रेटिंग को बीबीबी प्लस पर रखा था।

जनवरी में देश का निर्यात बढ़ा

निर्यात 5.37 फीसदी बढ़कर 27.24 अरब डॉलर रहा

नई दिल्ली। भारत ने बीते महीने जनवरी में पिछले साल के मुकाबले 5.37 फीसदी ज्यादा वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात किया जबकि आयात में 2.05 फीसदी का इजाफा हुआ है।

वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जनवरी 2021 में 27.24 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात किया जबकि जनवरी 2020 में देश से 25.85 अरब डॉलर की वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात हुआ था। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जनवरी के दौरान देश से वाणिज्यिक वस्तुओं का कुल निर्यात 228.04 अरब डॉलर मूल्य का हुआ है, जोकि पिछले साल के इसी अवधि के दौरान 264.13 अरब डॉलर था। इस प्रकार वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के 10 महीने में 13.66 फीसदी की गिरावट आई है। भारत ने जनवरी 2021 में 41.99 अरब डॉलर मूल्य की वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात किया है जबकि पिछले साल इसी महीने में 41.15 अरब डॉलर की वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात हुआ था। इस प्रकार वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात में बीते महीने सालाना आधार पर 2.05 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, वित्त वर्ष के आरंभिक 10 महीने में वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात 300.26 अरब डॉलर रहा है जोकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 405.33 अरब डॉलर से 25.92 फीसदी कम है।

फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर का अहम योगदान

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक निर्यात में सबसे बड़ा योगदान फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर का रहा। जनवरी माह में फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र का निर्यात 16.4 फीसदी और इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात 19 फीसदी बढ़ा। इसके अलावा जिन अन्य क्षेत्रों में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, उनमें खाने का तेल 253 प्रतिशत, लौह अयस्क 108.66 प्रतिशत, तम्बाकू 26.18 प्रतिशत, चावल 25.86 प्रतिशत, फल और सब्जियां 24 प्रतिशत, कालीन 23.69 प्रतिशत, हस्तशिल्प 21.92 प्रतिशत, मसाले 20.35 प्रतिशत, सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ 19 प्रतिशत, चाय 13.35 प्रतिशत, काजू 11.82 प्रतिशत, प्लास्टिक 10.42 प्रतिशत और रसायन 2.54 प्रतिशत। इसके अलावा जिन निर्यात क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई उनमें पेट्रोलियम उत्पाद 37.34 प्रतिशत, कपड़ा 10.73 प्रतिशत और चमड़ा 18.6 प्रतिशत शामिल हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरू किया अभ्यास

टीम के कोच रवि शास्त्री ने उत्साहवर्धक भाषण के साथ किया पूरी टीम का स्वागत

चेन्नई । भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शुक्रवार से इंग्लैंड के साथ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच की तैयारियों के लिए मंगलवार से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने उत्साहवर्धक भाषण के साथ पूरी टीम का स्वागत किया। उसके बाद टीम ने सीरीज की तैयारियों के लिए नेट्स पर अपना अभ्यास शुरू किया। बीसीसीआई ने ट्विटर पर अभ्यास की कई फोटो पोस्ट की है और उसने इसके कैप्शन में लिखा, चेन्नई में अभ्यास सत्र का पहला दिन।

मुख्य कोच रवि शास्त्री ने पूरी टीम का स्वागत किया और फिर उसके बाद उन्होंने उत्साहवर्धक भाषण भी दिया। सोमवार को दोनों टीमों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें आउटडोर ट्रेनिंग करने की इजाजत दी गई थी। क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद भारतीय टीम ने सोमवार शाम को अपनी पहली आउटडोर ट्रेनिंग की थी। कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया से लौटने वाली भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। कोहली पितृत्व अवकाश पर थे जबकि ईशांत चोट से उबर रहे थे। उनके अलावा तेज जसप्रीत बुमराह और आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी टीम से जुड़ गए हैं। भारत दौरे पर इंग्लैंड को शुरुआती दोनों टेस्ट चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलना है। पहला टेस्ट पांच से नौ फरवरी तक जबकि दूसरा टेस्ट 13 से 17 फरवरी तक खेला जाएगा। चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड ने अब तक नौ टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से मेजबान भारत ने पांच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड के हिस्से में तीन जीत नसीब हुई है।

टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को 2-0 से हराना होगा

दोनों टीमों के बीच 1982 में खेला गया मैच ड्रॉ रहा था। भारत को आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के साथ पांच फरवरी से होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतने की जरूरत है। अगर वह एक टेस्ट हार जाता है तो उसे इंग्लैंड के खिलाफ बाकी तीन टेस्ट जीतने होंगे। दूसरी तरफ, इंग्लैंड को भारत को 3-0 से हराना होगा। इंग्लैंड अगर 2-2 से ड्रॉ भी खेलता है तो वह आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका में भारत से आगे नहीं निकल सकता।

गिल और पंत जैसे युवा सितारों पर रहेंगी नजरें: कॉर्क

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डोमिनिक कॉर्क का मानना है कि भारत और इंग्लैंड के बीच पांच फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे युवा सितारों पर सभी की नजरें रहेंगी। इंग्लैंड के लिए 37 टेस्ट खेलने वाले और अब कमेंटेटर बन चुके कॉर्क ने कहा कि इस सीरीज में गिल और पंत जैसे युवा सितारों पर नजरें रहेंगी क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। कॉर्क ने कहा, हम इन दोनों युवा खिलाड़ियों को सीरीज में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल ने क्या लाजवाब प्रदर्शन किया। गिल एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं इसलिए मैं इन पर अपना दांव लगाना चाहूंगा। पंत की भी सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पंत ने ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट में सीरीज जिताने वाली जो पारी खेली थी वो वाकई बेहतरीन थी। इंग्लैंड को इन दोनों खिलाड़ियों पर ख़ास नजर रखनी होगी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को गिल को आउट करने के लिए ख़ास रणनीति तैयार करनी होगी।

भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं: लीच

इंग्लैंड के लेग स्पिनर जैक लीच का कहना है कि वह भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लीच पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ हुए दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शामिल थे जो लगभग पिछले एक साल के अंतराल के बाद उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था। लीच ने श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट लिए थे लेकिन उनका मानना है कि उनको अभी भी अपने प्रदर्शन में कुछ सुधार लाने की जरुरत है। लीच के अलावा इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर डोमिनिक बेस भारत के खिलाफ इंग्लिश टीम के स्पिन विभाग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बेस ने श्रीलंका के खिलाफ 12 विकेट झटके थे। लीच ने कहा, मैं भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं। श्रीलंका दौरे से पहले कई समय तक मैं मैदान से बाहर रहा था लेकिन उस दौरान मैंने बेहतर करने पर काम किया और जैसा गेंदबाज बनना चाहता हूं वैसा बनने की कोशिश की। श्रीलंका दौरा अच्छी शुरुआत थी और मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। हम सिर्फ हर मैच में टीम की मदद करना चाहते हैं और अन्य स्पिन गेंदबाजों को देखते हुए हमारी टीम बेहतर है और सभी के बीच अच्छे रिश्ते हैं। हम यहां सीरीज जीतने के इरादे से आएं हैं और मेरा ध्यान वहीं केंद्रित है। श्रीलंका में अपने प्रदर्शन के बाद लीच ने स्वीकार किया है कि उन्हें अभी अपने खेल में और सुधार लाने की जरुरत है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से स्पिनर होने के नाते दूसरी पारी में विकेट लेने से हमेशा आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जो कभी संतुष्ट नहीं होता और मुझे अभी अपने खेल में और सुधार लाने की जरुरत है।

रहाणे की जीत के बाद विराट की कप्तानी को देखना दिलचस्प होगा: पीटरसन

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्या रहाणे की कप्तानी में भारत की 2-1 की शानदार जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी को देखना दिलचस्प होगा। रहाणे की कप्तानी में भारत ने मेलबोर्न में दूसरा टेस्ट और ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम की थी। राष्ट्रीय चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले दो टेस्टों के लिए कप्तान विराट को सौंपी है और रहाणे का भी कहना है कि विराट हमेशा उनके कप्तान रहेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पीटरसन ने भारत और इंग्लैंड के बाच पांच फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज को लेकर कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में विराट की कप्तानी कैसी रहती है। रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार कप्तानी की थी और अब विराट कप्तानी संभालने जा रहे हैं। दोनों का तालमेल किस तरह काम करेगा, यह काफी रोमांचक होगा। भारत की टेस्ट कप्तानी के मुद्दे पर पूरी सीरीज के दौरान लगातार चर्चा जारी रहेगी। विराट इस समय भारत के सबसे सफल कप्तान हैं और वह दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हैं। रहाणे ने अब तक पांच मैचों में भारत की कप्तानी की है जिसमें से उन्होंने चार टेस्ट जीते हैं।

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए मर्व ह्यूज

टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग के शीर्ष पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की वापसी का एक अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं ह्यूज

मेलबर्न । पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग के शीर्ष पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की वापसी का एक अभिन्न हिस्सा रह चुके ह्यूज ने 1985-94 तक करियर में 53 टेस्ट और 33 वनडे मैचों में 28.38 की औसत से 212 टेस्ट विकेट लिए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, मर्व ह्यूज हम में से कई लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियाई समर का एक प्रतीक था। एक बड़ा-व्यक्तित्व, एक शानदार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, खेल के लिए एक राजदूत और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में एक योग्य प्रेरक। 1994 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे तेज गेंदबाज प्रथम श्रेणी में 14 सीजन तक विक्टोरिया और एसेक्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष अर्ल एडिंग्स ने कहा, मर्व ह्यूज ऑस्ट्रेलियाई खेल के दिग्गज हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय खेल को खेलने वाले महान गेंदबाजों में से एक था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम पहली बार 1995 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हॉल ऑफ फेम आधिकारिक तौर पर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड द्वारा शुरू किया गया था। ह्यूज के पूर्व टीम साथी और आस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रेड डायर ने कहा, मर्व ने मैदान पर वह सब कुछ दिया, जो पहली गेंद से लेकर आखिरी तक था। आप निश्चित रूप से जानते थे कि आप एक प्रतियोगिता में थे, यदि आप उनके खिलाफ खेल रहे थे और आपके पास 100 प्रतिशत प्रयास करने के लिए एक टीम साथी था।

साइकिलिंग में ओलंपिक रजत पदक विजेता सुरकोवस्की का निधन

वारसॉ । साइकिलिंग में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पोलैंड के रेजार्ड सुरकोवस्की का सोमवार को निधन हो गया। वह 75 बरस के थे। इवोना आरकुसेवस्का सुरकोवस्की ने कहा कि उनके पति का मध्य पोलैंड के रेंडम में एक अस्पताल में निधन हुआ। वह कैंसर से जूझ रहे थे। सुरकोवस्की ने पोलैंड की रोड रेस टीम के साथ 1972 और 1976 में पदक जीते। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भी तीन खिताब जीते जिसमें 1973 में गैर पेशेवरों की रोड रेस का व्यक्तिगत खिताब भी शामिल है। पोलैंड के साइकिलिस्ट माइकल क्वियातकोवस्की ने ट्विटर पर लिखा, लीजेंड। पोलैंड के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ राइडर। रेजार्ड सुरकोवस्की 1946-2021। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।